पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

www.samaymaya.com

पंजीयन क्रमांक RNI-MP\HIN\2006/20685

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

cell : 9300755803-9425125569
Phone Fax : 91-731-2530859
Websites : www.samaymaya.com
www.geocities.com/samaymaya/march09.pdf
www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com

(c) all copyrights reserved with chief editor,do not publish any matter without prior permission.

वर्ष 4 अंक 31 इंदौर, सोमवार 30 अगस्त से 5 सितम्बर 2010 तक पृष्ठ 8 मूल्य रु. 2/-

2 जी.एस.टी. के बहाने राज्यों को पंगु करने की साजिश

3 महाकाल और खजराना पर सरकारी डकैतों का साया

4 33बी.ओ.टी. के 60 टोल पर वसूली पू.प्र. मात्र 10 को

5 राष्ट्र में छोटे आग्नेय अस्त्रों की बाढ़ की तैयारी

6 पानी-नेताओं, पूंजीपतियों और सत्ताधीशों को

7 ग्रा.यां.से.के का.अ. गौर द्वारा स्टिंग आप्रेशन

अमेरिकी गिद्ध निगाहें ईरानी पेट्रोल पर

इस्रायल और अमेरिका की ईरान पर हमले की तैयारी

दुनिया अमेरिका की बपौती नहीं, परमाणु बमों की आड़ में गुंडागर्दी

अमेरिका की निगाहें एशिया के देशों की पेट्रोल संपदा पर पिछले ५०वर्षों से लगी है। १९६०-७० के दशक से ही उसने पहले ईरान और इराक को वर्षों तक लड़ाया फिर मध्यस्थता करने कुदा, सद्दाम को पाल पोसकर बड़ा किया। बड़ा होते-होते वह ईराक का शासक बन बैठा। और अमेरिका को ठेगें पर मार दिया। फिर कुवैत पर कब्जे की तैयारी में आ गया तो उसने ईराक को तबाह किया था परंतु सद्दाम की दृढ़ इच्छा शक्ति ने १० वर्ष में ही नया ईराक खड़ाकर दिया। उसने फिर कब्जा ही कर लिया और पूरा पेट्रोल हड़प लिया।

ईराक के बाद एशिया में दूसरी सबसे बड़ातल निर्यातक ईरान पर उसकी पिछले ४०वर्षों से निगाहें है। पिछले ७ वर्षों से उस पर परमाणु बमों के विकास के नाम पर हमले की तैयारी में बैठा है। बेशक इसके माध्यम से वो विश्व का गुंडा अपने हथियारों की भरमार क्षमता का परीक्षण समयावधि समाप्त होने

बमों।मिसाइलों का उपयोग और तीसरी तरफ एशिया के इस तेल निर्यातक पर हमला कर भारत, चीन जैसी एशिया की महाशक्तियां जो उसे आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका पर भारी पड़ रहे है तेल की आपूर्ति ठप कर उनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। दूसरी ओर अमेरिका को यह भी अखर रहा है। कि ईरान से पाइप लाइन से भारत की गैस आपूर्ति की व्यवस्था को कैसे रोका जाए।

बेशक भारतीय सत्ताधीश कांग्रेसी डकैत इस की आड़ में पुनः पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ाकर जनता को लूटने के अवसर की ताक में हैं। इसलिए भी वो अमेरिकी गुलाम अमेरिका को ईरान पर आक्रमण करने से नहीं रोकेंगे। तीसरी तरफ अमेरिकी एजेन्ट सोनिया भी कांग्रेसी डकैतों को अमेरिका के विरुद्ध ईरान पर आक्रमण के विरुद्ध नहीं बोलने देगी।

यदि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए यदि परमाणु हथियार बना भी रहा है। तो हर किसी को हक है, कि वह अपनी अपने राष्ट्र और जनता की सुरक्षा करे।

शेष पेज २ पर...

आत्म विश्वास और स्वाभिमान हीन गुलाम थे गुलाम रहेंगे

राष्ट्रगीत गुलामी का शिगूफे आजादी के

गीत गुलामी के गाएंगे, गुलामी फिर बुलाएंगे

राष्ट्र की आजादी को ६३ वर्ष गुजर गए, हमें और हमारे सत्ताधीशों को आजादी हजम नहीं हो रही। हम सड़कों पर तरीके से चलना नहीं सीख सके। तो जिंदगी में अपनी और अपने राष्ट्र की में कैसे तरीके से रह सकते है। सड़कों पर तरीके से स्वंपन चलना स्वमेव ही सिद्ध करता है। कि हमारी सोच क्या और कैसी है। जब हमारा वर्तमान सड़कों पर जानवरों की तरह चलने का है। तो स्वाभाविक है हमारा भविष्य भी जानवरों की तरह हंकने और हंकवाने का ही होगा।

इसका अंदाजा इस बात से बेहतर लगा सकते है। कि जो हमारा राष्ट्रगीत है। तो राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त रविन्द्र नाथ टैगोर ने १९१९ में जार्ज पंचम की आगवानी में लिखा था। जिसमें उस गुलामी पसंद ने न केवल जन गण मन से उस अधिनायक अर्थात हम जिन के आधीन से अंग्रेज रुपी नायकों की जय करवाई थी वरन् उसने उन्हें भारत का भाग्य विधाता भी बताया था। इसके साथ ही उसने पंजाब, सिंध, जबकि पंजाब का आधा हिस्सा और पूरा सिंध प्रांत अब पाकिस्तान में है। इसके विपरीत आजादी के ६३ वर्ष बाद भी हमारे तथ कथित राष्ट्रगीत का हिस्सा है। के साथ गुजरात,मराठा, द्रविड़ अर्थात दक्षिण के प्रांत, उत्कल अर्थात उड़ीसा, बंग अर्थात बंगाल के भी दो हिस्से हो चुके है। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश बन चुका है। पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा है। विंध्य अर्थात विध्यांचल पर्वत जो मप्र का हिस्सा है। यमुना और गंगा की जल की तरंगे भी अंग्रेजों की जय-जय कार करती है। ये सब आपके रस नाम का स्मरण कर आशीष मांगती है। धन्य है ऐसे धूर्त गुलाम को जिसने न केवल ऐसा गुलामों के द्वारा उन धूर्त चालाक अंग्रेजों की वंदना में न केवल गीत गाया और ६३ वर्षों से अभी तक ये महान ऋषियों मुनियों के विश्व को ज्ञान बांटने वाले राष्ट्र को १२५ करोड़ ये गीत गा रहे है।

लानत है ऐसी धूर्त मूर्ख और वर्तमान राष्ट्र की सत्ता के नेताओं को ६३वर्ष बाद भी गुलामी की गीत गाना बंद नहीं कर पाए और चिल्लाते है कि हम आजाद है। देश के संसाधनों का उपयोग कर ब्रिटेन के गुलाम राष्ट्रों के राष्ट्र मंडलीय खेलों का आयोजन कर यह सिद्ध करते है। कि हमारे आकाओं आपने भले ही देश का त्याग दिया हो। पर हम अभी भी आपके ही तलुतों का रसास्वादन कर जीवन यापन कर रहे है। आप की याद रानी की मशाल जिसे क्वींस बेटन से नवाजा गया है लेकर ही जीवन को प्रकाशित कर दौड़ लगा रहे है। ये हमारा गुलाम सरदार प्रधान मंत्री जो वोटिंग मशीन की जालसाजी से हमारा दुर्भाग्य मनमोहन अभी भी आप के नाम की न केवल माला जपता है वरन् राष्ट्र की पुनः गुलाम बनाने के लिए कानून भी

शेष पेज २ पर...

पिछले 5-6 वर्षों में हर प्राकृतिक आपदा में चीनी तंत्र का खेल

लेह के बादल फटने में चीनी षड़यंत्र

भारत के सत्ताधीश कमीशन खोर डकैत, केवल अपने ही राष्ट्र की जनता को लूटने, बेवकूफ बनाने में ये धूर्त कांग्रेसियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता विश्व में, ये अंग्रेजों की अवैध औलाद। जिन्हें अंग्रेजों ने जाने के ६२वर्ष पहले ही पैदा किया था। वर्षों में लूटकर इंग्लैंड नहीं भेजा उससे कई लाख गुना ज्याद में डकैत, कमीशन खोरी करके स्विस बैंकों में जमा कर चुके है।अंग्रेजों ने फूट डालों राज करो की नीति पर चलकर २५० वर्ष शासन करके भी इतना देश की बर्बादी नहीं की, किसी से कर्जा नहीं लिया।

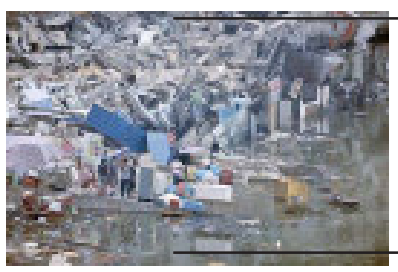

सत्ताधीशों की भ्रष्ट नपुंसक मान सिकता से शत्रुओं के बुंलद होंसले

शेष पेज ४ पर...

जब आरक्षण के नाम पर सामान्य का शोषण हो रहा हो?

जातिगत ही हो जनगणना

जबकि वोटों की गंदी राजनीति, और सरकारें बजट भी जातिवाद का आधार हैं।

पूरे भारत में वोटों की गंदी राजनीति और रण नीति का आधार ही जातियां हो, तो जनगणना में जाति क्यों नही लिखी और दर्शाई जाएगी। दर्शाई ही जानी चाहिए जातियां ताकि मालूम पड़ सके कि कौन अल्प संख्यक है। कौन बहुसंख्यक, कौन सी जाति के लोग आरक्षण के पात्र है। गरीबी अमीरी और पिछड़ापन हर जाति में समान रुप से फैला है। सारी अमीरी गरीबी और पिछड़ा पन शिक्षा से जुड़ा है। जो शिक्षित है, वे अपनी दशा और दिशा येन क्रेन प्रकरण हर हाल में सुधार लेते है, चाहे वो हिन्दुओं, मुस्लिमों, आदिवासी या हरिजनों में ही क्यों न हो?

दूसरी ओर जब शासकीय विभागों में नियुक्तियां, पदोन्नतियां, जातिगत आधार पर होती है। सभी से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर समान रुप से वसूले जाते है जबकि उनका खर्च, वोटों के लिए हरिजन आदिवासियों पर दुगुना तिगुना-किया जाता है, बेशक उनके नाम पर मंत्री, सत्ताधीश अधिकारी और कर्मचरी ही ७० प्रतिशत उकार जाते है, फिर भी जब बजट आबंटन अनुसूचित जाति, जनजाति पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है जातिगत आधार पर तो जनगणना जो १०वर्ष में एक बार होती है, पिछले ६० वर्षों में अभी तक क्यों नहीं की गई मात्र इसलिए ही न, ताकि जो जन धन को हड़पों की नीति की सच्चाई जन-जन तक न पहुंच जाए।

सामान्य जाति के जन अपने बल बूते पर पढ़ाई लिखाई दुगुनी कड़ी प्रतियोगिताओं में ८०-९०प्रतिशत की सफलताए प्राप्त करें डाक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी बन भी जाए तो एक ही पद पर ३०-३५ वर्ष तक सड़ते रहे। और नियुक्ति वाले पद से ही सेवा निवृत्त हो जाए और घर में, समान में ये सत्ताधीश धूर्त उन्हें मुंह दिखाने लायक भी न छोड़े, क्योंकि उनका अभिषाय है, कि वो सामान्य कुल में पैदा हुए थे, जब जातिगत आधार पर ये जुल्म आजादी के बाद से सामान्य वर्ग के लोगों पर पिछले ६०वर्ष से ढ़ाचा जा रहा हो, तो ६० वर्ष से होने वाली जनगणना में जातियां क्यों नहीं लिखी जा रही है। ताकि उन धूर्त सत्ताधीशों का जनता को भ्रमित करने और सत्ता हथियाने का गणित न गड़बड़ा जाए।जहां तक कांग्रेसी गिरोह का सवाल है,तो वह अंग्रेजो के द्वारा स्थापित इस गिरोह को जाते-जाते अंग्रेज फूट डालो राज करो हमने किया है तुम भी करों का जो सत्ता में बन रहने का गुरु मंत्र दे गए थे।

शेष पेज ५ पर...

सम्पादकीय

सत्ता लोकतंत्र की नहीं डकैत तंत्र की

वर्तमान भारत की सत्ता, सत्ताधीशों द्वारा वोटिंग मशीनों की जालसाजी से हथियाई है। स्वाभाविक सत्ताधीशों को सत्ता में बैङ्क कर चारों तरफ से धन बटोरकर स्थिर खातों में जमा करना ही उद्देश्य रह गया है। भारत की वर्तमान सत्ता डकैतों की है। जिनके सामने चंबल के भी हड़ों के डकैतों से लेकर समुद्री डकैत भी शर्मा जाए। चबंल के भी हड़ों के डकैत रु.२५-५० लाख में मान जाते है। समुद्री डकैत २५-५०करोड़ के खुश हो जाते है। अब हमारे यहां के डकैतों रु.१००-२०० करोड़ तो जीरो के समान है। अब ये डकैत पूंजी पतियों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हजारों करोड़ के कमीशन डकार कर भी चैन नहीं लेते।

सत्ताधीश डकैत पूंजीपतियों के इशारों पर काले कानून बनाकर जैसे जीएसटी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम ०६ बहुराष्ट्रीय कं. को दवा उद्योग सौंपने के लिए कानून बनाए जिससे इंदौर की ही ३०० और देशभर के ३०००० से ज्यादा दवा बनाने वाले छोटे उद्योगों को कानूनों के माध्यम से बंद करवा दिया और दवा उद्योग को बड़ी बहुराष्ट्रीय कं. से सैंकड़ों करोड़ डकार कर पूरा दवा उद्योग उन्हें, सौंप दिया गया ताकि वो जनता से दुगुनी-चौगुनी लूट कर सकें।

रु. ५०००० करोड़ की समुद्र में पड़ी सड़ रही पनडुब्बियों की खरीद की गई जिनकी कीमत रु.५००० करोड़ भी नहीं थी। जिसमें सीधा ही रु.२५००० करोड़ से रु.४०००० करोड़ हजम कर लिया जाएगा। रुस की गोद में पड़े १९८९ से सड़ रहे गोर्शकोव को पहले रु. ६०००० करोड़ में खरीदने का सौदा हुआ। डकैतों ने जालसाजी से सत्ता हथिया कर उसी सौदे को रु.१०००० करोड़ कर दिया। अब रु. ५००० करोड़ से ८००० करोड़ तक डकारा जाएगा। बेशक डकैत गिरोह का ऐसी डकैतियों में सबका हिस्सा रहेगा।

इन कड़े सौदों से लेकर रु. ८,१०, १२ प्र.कि. का गेहुं, चावल, जो उच्च श्रेणी का होता है।लेती में लेकर लाखों टन निर्यातता कर रु. १०/-से २० प्रति किलों का हजारों करोड़ में कमीशन डकार कर वहां से जानवरों के खाने से ज्यादा खराब सड़ा गेहूं खरीद कर हजारों करोड़ रु. का कमीशन डकार कर वहां से जानवरों के खाने से ज्यादा खराब सड़ा गेहूं खरीद कर हजारों करोड़ रु. का कमीशन डकार रु. २०/-प्रति किलो खरीदकर यहां की जनता को राशन के माध्यम से बंटवाया गया। दूसरी ओर पूंजिपतियों के माल और सट्टोरियों को घाटा न हो जाए। लाखों टन गेहूं सरकारी गोदामों में सड़या जा रहा है। उपर से जनता पर एहसान ये भी कि हम अनुदान दे रहे है।

इस प्रकार से लाखों करोड़ बटोर कर सत्ताधीश मंत्री,इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारी जो लाखों करोड़ के मालिक भी हो सकते है। जो केन्द्रीय सत्ता में बैङ्के है। राज्य की सत्ता में बैङ्के अधिकांश ९०प्रतिशत हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक है। इंडियन रेवन्यु ईटिंग सर्विस जो आयकर कस्टम एंड एक्साइज में बैङ्के हैं। साधारण सा निरीक्षक भी रु. २५-५० करोड़ की संपत्ति का मालिक है। यही हाल इंडियन क्राइम प्रोटेक्शन सर्विस के आईपीएस का है। रु. १००-२००करोड़ का मालिक हैं। जो डीएसपी और एसपी है या उपर है। इतनी संपत्ति होने के बावजूद इनके बच्चों की फीस भी सरकारी खजाने में से ही भुगतान होती है।प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी स्तर के मंत्रियों रुपी डकैतों से लेकर गांव का सरपंच यदि पढ़ा लिखा समझदार है, तो २-३ वर्ष में ही २-५ करोड़ का मालिक बन जाता है। आखिर ये बड़े पोश डकैतों का ही साम्राज्य है। अब लोक तंत्र कहने को है सत्ता चारों तरफ डकैत तंत्र की है।

जी.एस.टी. के बहाने राज्यों को पंगु करने की साजिश

गांधी की कांग्रेस विकेन्द्रीयकरण और स्वदेशी सोनिया की कांग्रेस सत्ता का केन्द्रीयकरण और पूर्ण विदेशी भारत में १९९० में जब विश्व व्यापार संगठन की चालों के सामने नरसिंहाराव की सरकार ने घुटने टेकने शुरु कर किए थे। तब ही से यह स्पष्ट होने लगा था, कि कांग्रेस पुनः विश्व व्यापार संगठन की चकाचों की षड्यंत्र कारी चालों में राष्ट्र की पुनः विदेशियों को शनैः शनैः सत्ता सौंपकर पूर्णतः कमीशन उकार कर, गिरवी करेगी और बेंच देगी।

विदेशी इशारों पर सन् २००४-०५ से पहले पूरे राष्ट्र में वाणिज्यकर या विक्रय कर को हटाकर वेट लगाया गया और अब वेट हटाकर वस्तु और सेवाकर थौप कर पूरे राष्ट्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की आय को अपने हाथों में केन्द्रिय कर समेटेगी और राज्यों को, यदि वे केन्द्र के इशारे पर नाचेंगे तो धन मिलेगा अन्यथा कुछ भी नहीं।

दूसरी और जिनसे केन्द्र में बैठे कांग्रेसी गिद्धों को मोआ धन मिलेगा उनको वहीं पर किसी भी कानून की आड़ लेकर या कानून बनाकर घूट दे दी जाएगी और देशी करोड़ों लोगों के धंधे करने वालों पर उल्टा ही टेक्स लाद कर उन्हें विदेशियों से प्रतियोगिता करने लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। छोटे उद्योगों, दुकानदारों को इस तरह से टैक्स लाद कर बर्बाद किया जाएगा। दूसरी तरफ राज्य सरकारों को जब आगम आय ही नहीं मिलेगी तो वो राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी वेतन भत्तों की समय पर अदामगी नहीं कर पाएंगे।

कांग्रेसियों को राष्ट्र हित न जनहित से कमी कोई लेना देना नहीं रहा उसे अपने हितों से मतलब रहा हैं। पहले अंग्रेज लूट कर ब्रिटेन धन भेजते थे तो भी काफी कुछ मानवीयता, ईमान धरम और कानून होता था। पान किया जाता था। अब

केन्द्र की भीख व दया पर निर्भर होंगे राज्य

बकि ये ही सत्ताधीश है। कानून इनकी मुठ्ठी में, और अन्य विदेशी बैंकों में पैसा, औश्र स्वर्ण जमा कर रहे है। जीएसटी लगाने के बाद में जो वालमार्ट जैसे फुटकर व्यवसायियों को भारत बुला रहा हैं। उनसे रु.१०००-२००० करोड़ डकार कर उन्हें पूरे राष्ट्र के फुटकर व्यवसाय पर नियंत्रण कर खुलीलूट का तांडव करने का न्यौता दे रहे है। भारत के करोड़ों दुकानदार व्यावसायियों से तो एक मुश्त चंदा वसूलना संभव नहीं इसलिए विदेशियों को बुलाकर उनके हाथ में फुटकर व्यावसाय की संपूर्ण श्रृंखला सौंप दी जाएगी। बिजली, सड़के, पानी, दाना सब विदेशियों को गिरवी किया जा रहा है। उन्हीं के इशारों पर केन्द्र और राज्य सरकारी की करा धान नीति बदली जा रही है। ताकि उन्हें पैर जमाने करा धान के झंझटों से मुक्त रखने और मोटी वसूली करने में परेशानियां न उठानी पड़े।

दूसरी तरफ आई टीसी ने बड़ी-बड़ी जमीनें घेरकर गांवों में हरियाली की जो विशाल दुकानदारी खोलकर किसानों के साथ जिस तरह से लूटना शुरु किया है उसका अंदाजा छोटे शहरों के कोनों पर हरियाल के किसी भंडार गृह में घुसकर देखा जा सकता है। जहां ट्रेक्टर से लेकर, जूते चप्पल तक डालर के भावों में उपलब्ध है। वहां फसल की खरीदी रुपयों में होती है। इस तरह से छोटे शहरों के गांवों में जाकर जमीने न केवल आई टीसी वरन् रिलायंस जैसी कंपनियों ने पट्टे पर ली जा रही है। अब ये कंपनियां अपने हिसाब से खेती करके कृषि उपजें पैदा कर अपने भावों पर बेंचने के लिए स्वतंत्र है। वैसे भी गांवों में नरेगा के ओ से खेती हर मजदूरों को औसतन रु. १००/-प्रतिदिन की मजदूरी मिलने पर उन्होंने खेतों पर काम करना छोड़ दिया है। यदि उनसे काम लेना है तो उन्हें अब रु. १५० से २०० रु. प्रतिदिन की मजदूरी चाहिए इसलिए बड़ी कंपनियों की यांत्रिकीय खेती के सामने पर परागत मजदूरों से खेती कराना महंगा पड़ता हे ये बड़ी कंपनी एक तरफ कृषि कारोबार से टैक्स का पूरा लाभ उठाएंगी तो दूसरी तरफ जीएसटी का फायदा ही फायदा भी उपर लेन-देन कर अंतिम छोर तक यहीं प्राप्त करेंगी। २०वर्षों तक खेती करने के बाद सुखाधिकार के अंतग्रत सारे खेतों पर स्वयं कब्जा जमा लेंगी। और किसानों को अपने ही खेत पर बंधुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।अब रु.१००-२०० करोड़ का कमीशन छोटे-मोटे उद्योग पति खदान माफिया सड़क माफिया, भूमाफिया ही भेंट कर देते है इसलिए अब उससे पेट न भरना स्वाभाविक है। इसलिए अब रु. १०००-२००० करोड़ की कमीशन चाहिए। इसके बदले में ये केन्द्र के कांग्रेसी डकैत राष्ट्र की समाजिक, आर्थिक प्रशासनिक न्यायालयीन, कानूनी सारी सामाजिक, आर्थिक प्रशासनिक, न्यायालयीन कानूनी सारी व्यवस्थाएं चौपट करने, बदलने, गिरवी करने बेंचने सबके लिए तैयार हैं। जैसे १० वर्षों में ही विक्रय कर से वेट और वेट के बाद जीएसटी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर केवल मोटा कमीशन खाने, ५ से १० करोड़ लोगों की रोजी छीनने, देश की जनता को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हंवाले राशन की लाइनों में खड़ा करने का षड़यंत्र रचा जा रहा हैं। भारत के दवा उद्योग को चौपट करने के लिए कानून बनाकर चुपके-चुपके सारा व्यवसाय रेन बेबसी, केन्द्रीता व अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिया गया।

खाद्य उद्योग को चौपट करने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. ०६लगाया जा रहा है। इससे भी बच गए तो जीएसटी के लिए दबाव बनाया जा रहा है राज्यों पर ताकि राज्य की सरकारें केन्द्र के पास हाथ फैलाए खड़ी रहे। उनकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा उठे। अभी भी आयकर कस्टम व एप्साइज ड्यूटी का कितना शेयरमिल रहा है जो मप्र व अन्य राज्यों से केन्द्र कमा रहा है।

इस्रायल और अमेरिका की ईरान पर हमले की तैयारी

पेज १ का शेष...

ईरान में अमेरिका ने पिछले छह-सात वर्षों में हर षड़यंत्र की चाल चली और हर चाल में अमेरिका ने मूंह की रवाई। जबकि अमेरिका ने ईरान में चुनावों के नाम पर भी उसे गृहयुद्ध में झोंकने की कोशिश तक कर डाली थी।अमेरिका को ईरान का न केवल पेट्रोल हड़पना है वरन् पूरी दुनिया पर पेट्रोल डीजल के मामले में एकाधिकार जमाकर पेट्रोल की कीमतों में भारी उछालाकर छोटे-मोटे देशों की अर्थ व्यवस्था की कमर तोड़ कर उनकी अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर अपना वर्चस्व दाता की तरह बना कर सबकों गुलाम बना कर जोतने की वर्षो पुरानी तमन्ना भी पूरी करना है।वर्तमान में पेट्रोल विश्व के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था का आधार है। यदि अमेरिका का उस पर कब्जा हो गया तो दुनिया स्वमेव उसकी गुलाम बन जाएगी।विश्व के सभी देशों को ईरान पर आक्रमण को रोकने के लिए एकजुट होकर न केवल अमेरिका का विरोध करना चाहिए। यदि अमेरिका के विरुद्ध सभी चुप रहे तो अमेरिका की गुंडागर्दी को, उसके विश्व के दादा बनने के यज्ञ में स्वयं को होम करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

ईरान के साथ ही पूरे विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी लग चुका है।कि अमेरिका ईराक की तरह परमाणु बमों की आड़ में आक्रमण कब कर लेगा। उसके कब्जे में आते ही भारत जैसे गुलाम मानसिकता के राष्ट्र की तो छोड़िए चीन, उत्तरी कोरिया, रुस जैसे राष्ट्रों के तेवर भी न केवल ढीले पढ़ जाएंगे वरन् चीन जैसे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा ही।

निःसंदेह रुस, चीन जैसे राष्ट्र ईरान को अप्रत्यक्ष रुप से सहयोग देंगे। परन्तु एशिया में इस्त्राल के साथ होने से साथ ही ईरान और अफगानिस्तान में अमेरिकी और मित्र राष्ट्रों सेनाओं के चलते ईरान चारों तरफ घिरा हुआ होने से आक्रमण होने की दशा में चीन और रुस का सहयोग भी ईरान को ३-४ महीने से ज्यादा युद्ध करने लायक स्थिति में नहीं रहने देगा।

वैसे भी ईरान पर आक्रमण में अमेरिका को न केवल ईरानी पेट्रोल वरन् ईरान से अफगानिस्तान तक जाने और दक्षिण एशिया में पैर जमाने के लिए समुद्री मार्ग से सोना, युद्ध सामग्री लाने का रास्ता चाहिए था, ताकि वह चीन रुस और भारत पर सटीक हमलों में सफल हो सके। ईरान पर अमेरिका कब्जा होते ही उसका ये वर्षों पुराना सपना तो साकार हो ही जाएगा साथ ही रुस को घेरने उस पर आक्रमण करना सोवियत रुस के अलग ही रुस को घेरने उस पर आक्रमण करना सोवियत रुस के अलग हुए राष्ट्रों में पैर जमाने का दीर्घगामी षड़यंत्र भी सफल हो जाएगा।

ईरान पर अमेरिकी और इसरायली हमले को रोकने के लिए रुस, चीन, भारत जैसे राष्ट्रों को अभी से अमेरिका के विरुद्ध माहोल बनाने के लिए हल्ला मचाना, दबाव बनाना शुरु कर देना चाहिए।

राष्ट्रगीत गुलामी का शिगूफे आजादी के

पेज १ का शेष...

बना चुका है जिसे हम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि.०६ के नाम से जानते है। आप अब पुनः अपनी ईस्ट इंडिया या इंडियन टोबेको कं. है। ने गांवों में अपने हरियाली के नाम से बड़े-बड़े भंडार खोले है। पुनः खेतों को किसानों को टुकड़े डालकर पट्टे पर लेकर पूरे प्रदेश और देश में लाखों एकड़ खेत ले चुके है। तालमार्ट के नाम से इस राष्ट्र के गुलामों के हाकने के पुनः तैयार हो जाए ये राष्ट्र अभी भी आपकी ही राष्ट्रगीत में वंदना करता है। ६३वर्ष की आजादी में इस राष्ट्र की जनता चलना नहीं सीख पाई आप आए इन जानवरों को हांके। वरना हम तो आपके नाम पर ही अभी भी इन गुलामों को हांक रहे है। यहां से धन वसूल कर स्विजर लैंड की बैंकों में हमने इतना जमा कर लिया है। कि हमारी आने वाली १०० से ज्यादा पीढ़ियां भी उसके ब्याज से ही पल जाएंगी। आपकी भेजी हुई इटालियन सोनिया एजेंट के इशारों पर ही देश चल रहा है। ऐ मेरे आकाओं आप हुकुम करें कि आपकी आगवानी में और मूर्ख, भुखेरे, लालची आत्मविश्वास और स्वाभिमान इन हजारों सालों के गुलाम अब इस राष्ट्र की ७० प्रतिशत आबादी शिक्षित है। और इन्हें अब कानून बना कर ही हांका जा सकता है। विपक्ष में चाहे कोई भी हो राष्ट्रवाद का रोनेवाली भाजपा में भी आप चिंता न कीजिए सब नंगे भूखों की फौज है। सबकों उनके मुंह के आकार का टुकड़ा डालकर मतदान होगा और सारे कानून आपके हित में बना दिए, जाएंगें। आप आए या बड़े आका अमेरिकी आ जाए हम सबका स्वागत करेंगे।

न केवल हम वरन् तैयार होने वाली हर फौज से जो अभी पैदल चलना सीख रही हो या दौड़ रही हो शिक्षा में प्रारंभ से पहले ही राष्ट्र गीत के बहाने अभी भी आपका ही जयगान करती है। भले ही ये सोना उगलने वाली धरती कुछ भी उगले अभी भी आपकी सेवा में वैश्वीकरण के माध्यम से आपको ही अर्पित किया जाता है। हमारे जानवरों को हम अपना अच्छीगुणवत्ता का गेहूं, चावल, दाल, गोदामों में सड़ा दे उन्हें नहीं खिलाते, उन्हें हम आपका वहीं सड़ालाल गेहूं उपलब्ध करवातें है जो आपके यहां के जानवर भी नहीं खातें और आपको सत्ता बेंचकर आपसे सड़ा महंगा खरीदते है। इसके लिए हम जानबुझकर कर्ज लेते है। हम अभी भी आपकी भीख पर पल रहे है। हमारा ज्यादा धन हम योजनाओं के माध्यमों से स्वयं हड़प कर, कमीशन लेकर स्विस बैंकों में जमा कर देते है।

अब हमारे यहां क्रांतियां नहीं होगी, अब आप ही देख लीजिए हमारे यहां २०००० लोगों को मौत की नींद सुलाने वालें एंडरसन को भी शासकीय विधान से हवाई अड्डे पर पहुंचाकर स्वदेश भी सुरक्षित पहुंचाया और आपकी शान से उस मुकदमें का फैसला २६ वर्ष बाद भी जो किया तो २ वर्ष की सजा और वह भी गुलामों को जिनको भी हमने तत्काल जमानत दे दी।

पहले आपकों गांवों से आजादी की अलख जगाने वाले जो थे नंगे भुखों की भीड़ से भागना पड़ा अब हमने उन ग्रामीणों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से घोर आलसी बना कर पंगु बनाकर अपने अधीन कर लिया है। साथ ही इस योजना के माध्यम से न तो वो भुखे मरेंगे और नही ं दोनों वक्त सालभर पेट भोजन करेंगे। जो क्रांति करें या आंदोलन कर आपके हमारे खिलाफ आवाज उठा सके। पूरे देश में ग्रामीणों को नरेगा के माध्यम से ऐसा नकारा बना दिया है। कि वे दूसरे कृषि भूमि स्वामी किसानों के खेत पर काम करना जाना पसंद नहीं करते। इससे छोटे किसानों को खेती करना मुश्किल पड़ने लगा है। इसलिए वो भी अपने खेत बड़ी कर्पनियों को पट्टे पर देकर, किराए पर निर्भर हो जिंदगी जीने लगा है या अपने ही खेत पर बंधुआ मजदूर बन मजदूरी कर रहा है।

जहां तक नक्सलियों का सवाल है। हमने अधिकांश नक्सली नेताओं को फर्जी मुठभेड़ों में मार डाला है। लेह से रंगून तक चीनियों के लिए सीमाए खोल रखी है उन्होंने मात्र ५० किमी तक ३००० किमी लंबी सीमा में अपने कब्जा जमा लिया है हम उनका प्रतिरोध नहीं करते है। मेरे आका गुलाम आखिर गुलाम है। हमारा हजारों वर्षों का सैकड़ों पीढ़ियों का चरित्र गुलामी का रहा है। छुटे होते ही आजादी मिलते ही जानवरों की तरह चलते है। हमने फुटपाथ बना भी दिए, तो उन्होंने वहां दुकानें खोल दी। बिस्तर लगाकर सोते और सड़कों पर लहराकर चलते है। ये हमसे नहीं हांके जाते है। पहले २५० वर्ष राज किया था अब जाप हमारे कानूनों की तरीके से ५०० वर्ष राज कर सकते है। अब हमने न केवल बाल विवाह बंद करवा दिए है। वरन् हमने शिक्षा के साथ ही कंडोम बंटवाने शुरु कर दिए है। विवाह की प्रथा पुरानी मानने लगे है। नारी शिक्षा को फैला कर नारियों को इतना सक्षम बना दिया है कि अब वो शादी की तो दूर छूने देने से पहले मोलतोल करती है। जहां तक पुरुषों की युवा पीढ़ी हो, या मध्य वय की घोर लालची घोर कमचारे, घोर स्वार्थी, पैसों की खातिर सब कुछ करने की तैयार आत्मविश्वास और स्वाभिमान हीन। जैसे ही आपने १७वीं शताब्दी में और पुनः ४वीं शताब्दी में राजकर सकते है। और अब तो ज्यादा आसानी से राज किया जा सकता है। वैश्वीकरण के दौर में तो जर जोरू जमीन की आप खुली खरीद कीजिए जो चाहे भोगिए बस हमें कमीशन दीजिए पूरा देश चलाइए। हम आपकी हर सुबह आपकी पिछले ६३ वर्षों से वंदनाकर रहे है।

शासकीय धूर्त गिद्धों की प्रसिद्ध मंदिरों में डकैती

महाकाल और खजराना पर सरकारी डकैतों का साया

दर्शनार्थियों से लूट पूरी-सुविधाओं तकलीफ देह और अधुरी

उज्जैन प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में चढ़ावे को हजम करने और प्रशासन के नाम पर दर्शनार्थियों से रु.१५१/- की सीधे प्रवेश के लिए वसूलीकर कैसे भरी तपती मई-जून की गर्मी में परेशन किया जा रहा है। इसका नमूना महाकाल मंदिर में आसानी से देखा जा सकता है। जिसके सीधे प्रवेश द्वार पर रु. १५१/- अति महत्वपूर्ण व्यक्ति, सीधे प्रवेश लिखा हुआ है। इस महाकाल मंदिर में हर वर्ष करोड़ों रु. का चढ़ावा सोना, चांदी आदि दान के रुप में प्राप्त होता है। जिसे जिलाधीश और उसके सफेद पोश डकैत, भारी भरकम खर्च दिखाकर झुङ्गे व्हाउचरों के आधार पर उकारते है। यहां बैङ्गा महाधूर्त शुभकरण शर्मा जिस पर पूर्व से ही सैकड़ों आरोप है। भ्रष्टाचार के और विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मंदिर के डेढ़ क्विंटल तांबे के पात्रों के चोरी जाने और बाले-बाले बाजार में बिकवाने का भी मामला सामने आया है।

सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर वैसे १००मी. की दूरी पर ही महाकाल थाना है। पर साथ ही में, प्रवेश द्वार पर भी पुलिस चौकी है जहां पर १०-२० कर्मियों का स्टॉफ तैनात रहता है। इसके विपरीत फिर भी यहां सुरक्षा के नाम पर यहां निजी सुरक्षा के भी सैनिक रहते है। स्वाभाविक है ५० का वेतन का देयक बनता है और मुश्किल से १० कर्मी तैनात रहते है। वहां का ये भ्रष्ट अधिकारी शुभकरण शर्मा आधे का वेतन निजी सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर डकार जाता है। सूत्रों के अनुसार मंदिर में चढ़ाने के धन से चढ़ने वाला प्रसाद आम दर्शनार्थियों को जो बाहर से आते है रु.५१/-,१०१/-,१५१/-,२०१/- में मिलता है। परंतु सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, को ये शुभकरण मुफ्त में भेंट कर अपनी करनी को छुपाने और बचाने में कामयाब हो जाता है। जबकि इसकी धूर्तता, भ्रष्टाचार और डकैती के किस्से महाकाल मंदिर से लेकर जिलाधीश कार्यालय में वर्षों से चर्चा का विषय रही है सूत्रों ने यह भी बताया कि इसकी धूर्तता और भ्रष्टचार के लिए पूरे महाकाल मंदिर परिसर में इसका गिरोह है यह गिरोह दान के रु,५०००/- प्राप्त करता है, और रसीद की दूसरी प्रति पर मात्र रु. ५०/-ही दिखाए जाते है। इस प्रकार साधारण दिनों में भी प्रतिदिन ५ लाखों का गोल माल किया जाता है।

पहले मंदिर के पंड़ित चढ़ावा डकारते थे और करोड़ों रु. की संपत्तियां बनाते थे, अब ये सरकारी डकैत मंदिर के धन पर डाका डाल रहे है। आखिर इस धन से अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम औषधालय और चिकित्सालय क्यों नहीं चलाए जा सकते है। इस बार प्रशासन ने सोमवार को महाकाल की नगर दर्शन यात्रा में पास की व्यवस्थाएं लगा दी है। बिना पास के कोई भी सावन सोमवार की सवारी में शामिल हो नहीं हो सकेगा। जबकि उज्जैन में महाकाल की सावन की नगर दर्शन यात्रा में शामिल होने के लिए शासन सभी शासकीय विभागों में आधे दिन का अवकाश घोषित करता है। बेशक यह भी सच है कि ९० प्रतिशत कर्मचारी और अधिकारी कोई भी उस यात्रा में शामिल नहीं होता और आधे दिन की छुट्टी का लाभ सभी उङ्गाते है। पुलिस वालों और प्रशासन के एक दो अधिकारी ही व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही उसमें शामिल होते है।तो क्या उज्जैन का प्रशासन जब आधे दिन की छुट्टी घोषित करता है, तो क्या सबको पास भी जारी करता है वह तो पिछले दो तीन सोमवारों में कभी नहीं हुआ। हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से किया गया हो। परंतु वहां भी पासजारी करने के लिए वसूली तो शुरु हो ही गई दर्शनार्थियों से जो बाहर के दर्शनार्थी आते है। यदि बाबा महाकाल की नगर यात्रा में शामिल होने के लिए भी भेंट चढ़ाए जब पास जारी होते है। वैसे भी उज्जैन के भ्रष्ट प्रशासन का उद्देश्य तो यही है, कि आने वाले कुछ वर्षों से पासों की भी बिक्री की जाए।

आम दिनों में दर्शनार्थियों को ये श्वान धन नोंचने के लिए २ किमी लंबे घेरों में, जालियों में क्यों ढकेलते है। कई दर्शनार्थी इस पीढ़ा से बचने के लिए शिखर के दर्शन करके ही लौट जाते है। पर इन शूकरों को इससे क्या पड़ता है।

ये बत्तमीजीयां, प्रताड़नाएं ही हिन्दुओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करती है। पहले पंडों के, अब इन शासकीय डकैतों के चलते आम गरीब, असहाय वृद्ध, अपाहिज महाकाल के दर्शनों से कैसे प्रताड़ित किए जा रहे है। भाजपा जो हिन्दुओं की हितैषी बनने का ढ़ोंग और पाखंड करती है,स्वयं हिन्दु मंदिरों में कैसे भ्रष्टों, पाखंडियों को संरक्षण देकर कैसे हिन्दुओं को दर्शनों के लिए भी कैसी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देती है उसका ये ज्वलंत प्रमाण है।

दूसरी तरफ भाजपा के ही शासन काल में

सिंहस्थ के लिए आरक्षित भूमि पर धड़ले से प्लॉट काटे व कालोनियां बनाई जा रही है। भाजपा के मंत्री, विधायकों से लेकर जिलाधीश, नगरनिगम उज्जैन, उज्जैन विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम निवेश, पंजीयक मुद्रांक, सहकारिता के निरीक्षकों से लेकर अंकेशक, उप पंजीयक जिला पंजीयक, संयुक्त संचालक सब दोनों हाथों से धन बटोर कर सब मौनी बाबा बने हुए है।

वहीं हाल इंदौर के एकमात्र गणेश मंदिर खजराना के भी है। यहां भी सरकार डकैतों को धन हजम करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे है पर इन सरकारी डकैतों ने यहां भी पानी की व्यवस्था तक नहीं की है। खजराना मंदिर के चारों तरफ बनी प्रसाद की दुकानों में चारों तरफ मिलावटी लड्डू, पेड़े और मिङ्गाई की भरमार है। जो शुद्ध घी की मिङ्गाई और लड्डू के बोर्ड लगाकर रु.१६० से २५०/- प्रति किलों तक की वसूली कर रहे है। पर सच समझने वाला जनता है, कि जिस शहर में लाखों लीटर नकली दुध बिक रहा हो। शुद्ध घी के नाम पर क्या बेंचा जा रहा होगा अंदाज लगाया जा सकता है।बेशक नगर निगम के, खाद्य और औषधि निरीक्षक विभाग केश्वान, खाद्य निरीक्षकों को ये ईमानदारी से टुकड़ा डालते है।

भाजपा ने अपने शासन काल में प्रदेश के इस प्रकार ५० जिलों के अनेकों हिन्दु मंदिरों पर कब्जाकर डकैती और लूट खसोंट तो शुरु कर दिया दूसरी तरफ हिन्दुओं को अपनी लूट और वसूली के चलते इस प्रकार से दर्शनों के लिए भी शारीरिक और मानसीक प्रताड़ना देकर हिन्दु धर्म परिवर्तन की राह खोल दी ताकि इन प्रताड़नाओं से तंग आकर आम गरीब हिन्दु स्वयं धर्म परिवर्तन करे। क्योंकि परमेश्वर में आस्था मानवमन कर स्वाभाविक गुण है। वह एक धर्म में प्रताड़ित होगा तो दूसरे को अपनाएगा ही।

इसके साथ ही जिस प्रकार शुरु किया या करवा दिया है अगर औकात हो तो भाजपा मुस्लिमों, ईसाईयों के धर्म स्थलों पर कब्जा कर उनकी धन संपत्ति को नियंत्रण में लेकर दिखाए।

खाद्य व औषधि-मुखेरे डकैतों का अड्डा

मंत्री, नियंत्रक, निरीक्षक सबकों चाहिए धन

धन खर्च कर, मनचाही पोस्टिंग, नियम विरुद्ध वरिष्ठ का दर्जा

म.प्र. में शिवराज का प्रशासन अंधे पीसे कुत्ते खाएं, सिद्ध हो रहा है। अंधे प्रशासन में नियम कानून केवल वसूली का शस्त्र बन चुके है। यहां तक कि खाद्य वस्तुओं और औषधियों की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाला खाद्य व औषधि प्रशासन नियंत्रक राकेश श्रीवास्तव से लेकर २५० से ज्यादा खाद्य निरीक्षकों, ८० से ज्यादा औषधि निरीक्षकों रुपी भेड़ियों का तो अड्डा बन चुका है जहां जहर को भी अमृत सिद्ध किया जाता है। इंदौर में बैठे भुखेरे भेड़िए खाद्य निरीक्षक सचिन लोंगरिया को ४ वर्ष भी इंदौर से स्थानांतरण न किया जाना यह सिद्ध करता है कि इस विभाग के साथ ही पूरे स्वास्थ्य विभाग में हर कदम-कदम भेड़ियों का ही साम्राज्य है। चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री यहां प्रशासन अंधे पीसे, कुत्ते खाएं की तर्ज पर ही हो रहा है।

खाद्य निरीक्षक सचिन लोंगरिया के बारे मे विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसने रु.५ लाख खर्च कर न केवल स्थानांतरण रुकवाया वरन वरिष्ठ निरीक्षक का पद भी उसे नवाजा गया। आखिर ये भ्रष्ट इसके पिछले ४ वर्षों में इसने जितने नमूने लिए उसके असफल नमूनों में कितने प्रकरण न्यायालयों में प्रस्तुत किए और कितनों से इस हरामखोर ने लेन-देन कर झुंडे कर दिए। पर नियंत्रक रुपी मुखेरे राकेश श्रीवास्तव जो कि मुख्यमंत्री और उसके प्रमुख सचिव इकबाल बैस का कृपा पात्र है। को यहां बैठाया ही इसलिए गया कि वो भूखा खान चारों तरफ से वसूली कर सके। उसको अनेकों बार सूचना के अधिकार में पत्र दिए गए। अब ये जालसाजों का भोपाल स्थित मुख्यालय का अड्डा न केवल हजम करने लगा है। वरन् मुख्य सूचना आयुक्त पद्मपाणि तिवारी को भी भेंट पूजा चढ़ाकर अपीले भी निरस्त करवाने लगा है।

नियंत्रक रुपी भूखे भेड़ियों राकेश श्रीवास्तव को यहां बैठे २ वर्ष से ज्यादा बीत चुके है पर इस हरामखोर ने धन की खनक में अभी तक ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट १९४० और खाद्य का खाद्य अपामिश्रण निवारण अधि. १९५४ की एक बार दोनों को उड़ती निगाहों से भी नहीं पढ़ा है पदोन्नत भारतीय गाली देने वाली प्रशासनिक सेवा या आंगल में इंडियन एब्यूसिंग सर्विस का ये अधिकारी नियम कानूनों की आड़ में केवल वसूली में गोंच की तरह चिपट कर केवल धन बटोरने में लगा है।

इसके पूरे प्रदेश में फैले २५० से ज्यादा खाद्य निरीक्षक, निरीक्षक और नमुने लेने की धमक चमक दिखाकर, इंदौर जैसे शहर में सचिन लोंगरिया जैसे खाद्य निरीक्षक रु. ३ से ५ लाख महीना वसूलकर लाख रु. महीने की भेंट केवल नियंत्रक को ही चढ़ा देते है। बाकी इंदौर के ८ निरीक्षक है जो भी रु. ५०००/-से लाख रु.की वसूली कर रहे है। उपर से स्थानांतरण के सत्र में उज्जैन का महाभ्रष्ट खाद्य निरीक्षक भी रु.३ लाख खर्च करके इंदौर आ गया है। इसका और इंदौर के सचिन लोंगरिया के भ्रष्टाचार से महीना वसूली रुकते ही नमूने लेने की धमकी नमूना लेने के बाद सीधे ५० हजार, लेने के बाद रु.५००००/- मिलने के बाद नमूना बदलने, छुट्टीयों के दिन भी करना, नमुनें के बंडल लेजाकर घर रख लेना। ये काम देवास में पदस्थ सुषमा पथरो इसने भी अपना स्थानांतरण रुकवाने जबकि इसे ४ वर्ष से ज्यादा हो गया रु.३ लाख दिए भी करती है।

इंदौर, देवास, उज्जैन, पीथमपूर से यहां के खाद्य निरीक्षक तो वसूली करते ही है। परंतु वसूली की लार तो भोपाल

वालों की भी टपकती है। अभी हाल ही में भोपाल का संयुक्त संचालक स्तर का निरीक्षक दिनेश श्रीवास्तव इंदौर का सचिन, ङ्गाकुर, स्वामी गुप्ता सभी धार का सोलंकी ने मिलकर अलग टीमों में ५० से ज्यादा स्थानों पर दबिश देकर करीब रु.१० लाख की वसूली लगभग सभी खाद्य उद्योगों से की और जब भास्कर ने पूछताछ की तो ८ मात्र फैक्ट्रीयों के नमूने लेना बता दिए जबकि इन लुटेरे भेड़ियों के साथ कोई भी नमूना लेने वाला सहायक नहीं था, ताकि डकैतों की चौथी वसूली में न केवल विघ्न न आए और किसी फैक्ट्रियों में गए कहां से कितनी वसूली हुई ये बात पत्रकारों तक न पहुंच जाए। चूंकि सभी माध्यम दर्जे के उद्योग है। इसलिए जो नमूने लिए गए है अब उनसे चूंकि संयुक्त नियंत्रक निर्देश श्रीवास्तव का प्रादेशिक स्तर का डकैत है। नमूने बदलने के रु. २ लाख नमूने पास करवाने की ग्यारंटी के और यदि २ लाख नहीं दिए तो

नमूने फेल होंगे ही, तो प्रकरण दबाने के रु.३ लाख की ८ फैक्ट्रियों से वसूली हो ही जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग का इंदौर का महाजालसाज डकैत श्रेष्ठ डॉ. पंडित जो अब संयुक्त संचालक स्वास्थ्य का पदभार भी संभाले है। मुख्य चिकित्साधिकारी होने के कारण जो नमूने लेने की पर्चियां उसके हस्ताक्षर से जारी होते है प्रति पर्ची रु.१००/- के हिसाब से ये भेड़िया भी हर खाद्य निरीक्षक से चाहे वो खाद्य एवं औषधि के हो या नगर निगम के वसूली कर लेता है तभी नमूना पर्चिया जारी की जाती है। अर्थात १० निरीक्षक खाद्य व औषधि के व १० नगर निगम के हर महीने रु. २००००/- डॉ. शरद पंडित को हस्ताक्षर करने की कमाई चाहिए।

पूरे प्रदेश में २५० निरीक्षकों को २५०० नमूने लेना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। यदि हर महिने २५०० नमूने लिए जाएं तो ९० प्रतिशत नमूने निश्चित तौर पर फैल होते है। परंतु सारे डकैत निरीक्षक जिनमें महिलाएं वसूली में पुरुषों से आगे है। जिसका उदा. देवास की खाद्य निरीक्षक सुषमा पथरोल है। अब साथ में इंदौरी खाद्य निरीक्षक सचिन लोंगरिया की पत्नी खाद्य निरीक्षक निर्मला सोमकुंवर भी देवास में भी पदस्थ है। अरविंद पथरोल और सुषमा पथरोल की उज्जैन और देवास में और अपने गृह नगरों में कुल संपत्ति नगद और अन्य में निवेश करोड़ रु. के आसपास है ये वहीं सुषमा पथरोल जिसने संजना जैन एडीएम की हल्दी कांड में लाखों रु. डकार कर ट्रांसफर करवाने में यह भूमिका निभाई थी। इस खाद्य और औषधि निरीक्षक के मुख्यालय में बैठे भूखेरे भेड़ियों राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त नियंत्रक दिनेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों प्रयोगशाला प्रभारी श्रीवास्तव, आरपी मिश्रा सबको धन बॉट कर आप जो चाहें करवा सकते है। और हो रहा नमूने तक प्रयोगशाला में शुद्ध नकली घी, दूध, क्रीम से लेकर नकली केसर, मिलावटी खाद्य तेलों नकली मावे की मिठाइयों से लेकर शुद्ध जहर के तक पैसे देकर न केवल पास कारवा लीजिए वरन् मानव उपयोग के लिए स्वीकृत कर वाली जिए।

इस मुख्यालय में बैठे हरामखोरों को वसूली से इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि ये निकंमी फौज ये भी देखले, कि कितने नमूने फेल हुए और गंतव्य तक पहुंचने के बाद जिलों में बैठे खाद्य निरीक्षकों ने कितनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसमें ५० से ८०प्रतिशत का अंतर है। इस आधार पर ९०प्रतिशत खाद्य निरीक्षक निलंबन और सजा के पात्र है। देवास की खाद्य निरीक्षक सुषमा पथरोल ने पिछले ४ वर्षों में ही हर वर्ष ७० प्रतिशत फेल नमूनों में संबंधित खाद्य विक्रेता से मो.लेन देन कर वो रिपोर्टस ही कार्यालय से गायब कर दी और न्यायालय में प्रकरण लगाने का मामला ही खत्म हो गया।

आखिर जिलों में बैठे महाजालसाज मुख्य चिकित्सा अधिकारी जैसे मानवों को नोंचने वाले भेड़ियों तक का यह कमाल है, कि वो खाद्य निरीक्षकों से पर्ची लिखने की वसूली से लेकर नमूने लेने और छोड़ने की वसूली के हिस्सेदार तो होते है। पर इस विभाग में क्या कहां हो रहा है कभी नहीं देखते।

लोकायुक्त में बैठे भुखेरों को इस बात की शिकायत की गई इस खाद्य एवं औषधि विभाग में कदम-कदम पर जालसाजियां कर वसूली हो रही है। कम से कम वो मप्र की खाद्य प्रयोगशाला से फेल नमूनों की कापियां निकलवा कर संबंधित जिलों के खाद्य निरीक्षकों और औषधि के मामलों में ये तो देखें कि कितने प्रकरण न्यायालयों में लगाए जिन्होंने प्रकरणों की प्रस्तुति में हेरफेर की है उनके विरुद्ध चालान पेश करें तो पिछले २-३ वर्षों के प्रकरणों में ही ९०प्रतिशत खाद्य निरीक्षकों का निलंबन करना पड़ेगा परंतु ये सब भी महीना डकारकर अजगर की तरह पचाने के लिए सीटों से चिपके पड़े है। काम धाम क अजगर के तरीके से ही करते है। भास्कर व अन्य सामाचार पत्रों को धन बांटकर डकैत सचिन अपनी तरीकें जपवा रहा है। अपने कुकर्मों को ढ़ाकने और वसूली बढ़ाने के लिए कहां से क्या सैंपल लिए

फैक्टरी	कंपनी सैंपल
बाबू सुपारी	सुपारी
माधुरी रिफायनरी	सोयाबीन, वनस्पति, सरसों तेल
लक्ष्मीनारायण इंडस्ट्रीज	लालकिला तेल, सरसों तेल
दीपक इंडसट्रीज	सरसों व नारियल तेल
पारस कंसेक्श्नरी	ग्लुकोज व टॉफी
धनंजय कंसेक्शनरी	कोका सॉलिड, सोया लेसीथीन
नोटी फुड प्रोसेसर लि.	ग्लुकोज, चॉकलेट, मगरीन
एमएसएस फुड प्रोसेस	सुपारी

म.प्र. रोड डकैत कारपोरेशन

33बी.ओ.टी. के 60 टोल पर वसूली पू.प्र. मात्र 10 को

सत्ता के डकैत तंत्र ने एक मुश्त वसूली कर, जनता को लूटने सड़के बेंची

भोपाल। म.प्र. सड़क विकास निगम सड़क विकास के नाम प्रदेश के सार्वजनिक राज्य के राजमार्गों को गिरवी करने और बेचने पर तुला हुआ है। जिसका व्यापक अनुमत और कटुअनुमत जनता को अब होने लगा है।

इस सड़क डकैत निगम में बैठा हर इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारी, लो.नि. मंत्री, और मुख्यमंत्री इन सड़कों को ठेकेदारों को जानबूझकर मोटी रकम वसूलकर वास्तविक एसओआर से कई गुना ज्यादा लागत के प्रावकलन बनवाकर सौंप रहे है। ताकि लागत के हिसाब से, वाहन चलाकों से वसूली की जा सके। दूसरी ओर पहले ये ठेके मात्र १० वर्ष के लिए सौंपे जाते थे, बाद में १५ वर्ष के लिए और अब ये ३०-३० वर्ष के लिए सौंपे जा रहे है। यहां बैठने वाला हर डकैत प्रबंध संचालक चाहे वह राघव चंडा, मोहंती, सुलेमान और वर्तमान विवेक अग्रवाल हों जिसमें कोई भी प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं था। न ही इन हरामखोरों को सड़कों की इंजिनियररिंग से, उसके स्तर किसी से मतलब नहीं होता इन डकैतों को मतलब होता है। तो मात्र इनकी वसूली से। इसके लिए ये सभी प्रकार की जालसाजियां करने ठेकेदारों के एजेन्ट बन नाचते है।

इसके लिए इन सभी इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारियों ने ठेकेदारों को रायल्टी भरने, वेट, आयकर, वृत्तिकर आदि तक से भी मुंह मोड़ लिया। जबकि इन जालसाजों ने सभी इस्टीमेट्स में इन सभी करो, रायल्टी आदि को ध्यान में रखकर ही इस्टीमेट का आंकलन किया होता है। इसके विपरीत पूरे प्रदेश में इन हरामखोरों ने उस रायल्टी में चूंकि अरबों रु. की बंदर बांट कर ली होती है। इसलिए उसे चुकाने के लिए नहीं कहते है। जबकि ये उसके नियोक्ता होते है। ऐसी सैंकडे, जालसाजियां करवाते रहते है। जहां तक वहां बैठे मुख्य अभियंताओं, संभागीय अभियंताओं या संभागीय प्रबंधकों और सहायक प्रबंधकों का सवाल उठता है। तो ये सारे हरामखोर उनके साथ पालतु श्वानों से बदतर व्यवहार करते है। जिस काम के लिए उन्हे वहां बैठाया जाता है। उस काम की अपेक्षा पूरे प्रदेश के हर संभाग में बैठा संभागीय प्रबंधक उपप्रबंधक, सहायक प्रबंधक की यहां कोई औकात वख्त नहीं होती, उन्हें यहां हॉ, जी सरकार बनकर एक तरफ एमडी की ओर दूसरी तरफ ठेकेदार की कठपुतली बन दिन गुजारने पड़ते है क्योंकि ठेकेदार एमडी को मोटा कमीशन बांट चुका होता है।तो वो सारे कुकर्म करने के बाद भी तो खुलकर अपने तरीके से काम करता है। सड़कों को एक बार बनाकर पूर्णता प्रमाण पत्र लेकर उसका उद्देश्य केवल वसूली करना होता है। माड़ में जाए सड़क सुरक्षा, वाहन चालकों की सुरक्षा, उसकी बला से दूसरी ओर ठेकेदार इस्टीमेट कितने का भी बनाए कैसा भी बनाए काम तो न्यूनतम लागत पर काम चलाउ ही करता है। जहां तक सलाहकार एजेन्सी का सवाल है, तो वहां भी बैठे तो आदमी ही होते है।

उनको भी टुकड़ा डालकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। बाद में ठेकेदार मनमानी करता है कोई मानक स्तर नहीं इंदौर बुरहानपुर मार्ग पर ७ वर्ष से वसूली चल रही है। दोनों तरफ ५-५ फूट की कच्ची मुर की पट्टियां सड़क के तल से मिलाकर अभी तक नहीं बनाई गई है सड़क के तल से दांए-बांए १ फुट से ज्यादा नीचा होने पर तल से मिलने तक वेरीकेडस पत्थरों तक को, रिटेनिंग वाल तक की व्यवस्था अनेकों स्थानों पर ७ वर्ष बाद भी नहीं की गई है हर वर्ष टोल टेक्स की राशि बढ़ाकर वसूलने में कोइ ताही नहीं बरती जाती। ये सब इन हरामखोरों को नहीं दिखता यहीं हाल प्रदेश की हर सड़क का है। खुले में डकैत निगम जनता की जगक पर डकैती डलवाकर अपनी वसूली कर रहा है।

इस नियम की जालसाजियों का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है, कि इसकी अपनी इंटरनेट साइटों पर ही उनके द्वारा डाली सारी सूचनाएं कुछ बताती है कभी बताने लगती है। अपने ही डाले डाटा को, अगली बार ये स्वयं ही झूठा सिद्ध करते रहे है।

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने, पर ये डकैत निगम कभी भी न केवल पूरी जानकारी नहीं देता वरन् अपनी जालसाजी के पन्ने भी गायब कर देता है। जब सारी जानकारी की फोटोकापी देना ही नियम है, तो कैसे और क्यों अपनी सच्चाइंया छुपाने के लिए जानकारी बनाकर देता है। ये सब दस्तावेज सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी में प्राप्त हुए है।

सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य हाथ लगे है। उसमें जालसाजियों का एक नया ही रुप सामने आया। जिसमें

मात्र १० बीओटी ठेकेदारों को बिना इंडियन रोड कांग्रेस के सड़कों के स्तर औश्र मानदंडों को ५-६ वर्ष बाद भी १०/५/२०१० तक पूर्णता प्रमाण पत्र दिए गए जबकि ३३ बीओटी की सड़कों के लगभग ६० से ज्यादा टोल बुथों पर वसूली की जा रही है। दूसरी ओर सूचना के अधिकार में जो जानकारी भेजी गई है वह बिना लेटर हेड के होने के साथ ही यह भी नहीं बताती है कि वह पत्र किस विभाग ने किसको जारी किया है। अर्थात यहां बैठे जालसाज प्रबंध संचालक अपने आप को बचाने के लिए कैसी और किस स्तर की जालसाजियां अरबों रु. हर साल कमीशन में डकार कर कैसे जालसाजियां कर रहे है। ये इनकी जालसाज मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। इन्होंने जो पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए उनके उदाहरण देखिए।

(१) एमपीआरएसएनएन/ जे-ई/ रोड़/ २००४/ १५६९ दि. १७/९/०४ इंदौर बुरहानपुर-इदिलाबाद,२०३ किमी, कुल रु. ६३ करोड़ का प्रोजेक्ट अनुदान स्वीक्रत रु.४५ करोड़। जबक इस सड़क के कुछ हिस्सों पर सित. अक्टू. ०३ से ही वसूली शुरु हो गई थी। पूर्णतः प्रमाणपत्र जारी किए ६ वर्ष के बाद भी निविदा की ओर बीओटी की शर्ते न केवल पूरी नहीं हुई इस मार्ग हर दिन एक दो वाहन अपर्याप्त सुरक्षा के चलते दुर्घटना के शिकार हो रहे है। पट्टीयां दोनो तरफ ५-५ की अभी तक न तो भरी गई है और नहीं किमी तक उनका अता पता है। सड़क के दोनों और ढलान के चलते सैंकड़ों वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे है परंतु रिटेनिंग वाल्स, वेरी केड्स का अता पता नहीं है। यहां तक कि मील के पत्थरों तक कई किमी पर न केवल नहीं है वरन् जो है उनकी रंगाई पुताई और फिर से लिखे भी नहीं गए है। साथ ही किसी भी टोल बूथ पर न तो स्नानागार, शौचालय, मूत्रालय, मूफ्त पीने का पानी, एंबुलेंस, क्रेन कुछ भी नहीं पाए जाते है। जबकि पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए ६ वर्ष बीत चुके है। लीन टोल बूथों पर एग्रीमेंट के अनुसार वसूली करनी चाहिए थी ये रोड डकैत कार्पोरेशन की सहमति और बंदर बांट के चलते ५ पर वसूली की जा रही है। हटाने के नाम पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर में अटका रखा है पिछले चार वर्षों से। अर्थात ठेकेदारों के साथ मिलकर एमडी कमीशन डकार कर वाहन चालकों की जेब पर खुले में डाके डाल रहा है। यही हाल इन डकैतों का पूरे प्रदेश में है उपर वसूली २००५ से ही शुरु हो गई थी। (२) पूर्णता प्रमाण पत्र क्र.एमपीआरीडीसी/ यू-जे/ रोड़/ २००५/ ९४९ भोपाल दि. १४/१/०५ को अंग्रोह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि. महू इंदौर को उज्जैन-आगर-सुसनेर-झालाबाड़ मार्ग को १३४ किमी पर जारी किया गया इसमें रु. २२.३२ करोड़ का अनुदान किया गया। मार्ग पर पेंच वर्क भी टाइम पर नहीं होता रिनोवेशन तो बहुत दूर की कोड़ी है । २ टोल बूथों पर वसूली। (३)पूर्णता प्रमाण पत्र क्र. एमपीआरडीसी/ जेएनपीआरडी/ ०७/ ६२८कि. ३.०५.०७ रीवा टोलवे प्रा.लि. के हैद्राबाद को रीवा-जयसिंग पुडा नगर-शहडोल-अमरकंटक मार्ग २४२.७० किमी इस पर अनुदान रु. ५३.५ करोड़। ३टोल पर वसूली ०६ से शुरु। (४) पू.प्र.क्र. एमपीआरडीसी/ जेएनपीआरडी/ ०७/ ६२९ दि. ३/५/०७ सतना मेहर-उमारिया मार्ग १२९.२१ किमी में. रीवा टोल वे प्रा.लि. हैद्राबाद अनुदान रु. २९८.१० करोड़, ३टोल बूथों पर वसूली अक्टू. ०५ से ही शुरु। (५) पू.प्र.क. ३४/एमपीआरडीसी/ एचएचके/ ०७-०८/ ६७९ दि. २/६/०८ को होशंगाबाद-हरदा-खंडवा १८५.६ किमी अनुदान रु. ५१.०३ करोड़ मैं. एमएस के इंफ्रास्ट्रक्चर न टोल ब्रिज प्रा.लि. को यह सड़क मात्र यह सड़क भी मात्र १५ चौड़ी है। इस हरामखोर ने भी वसूल सन् २००६ से ही वसूली शुरु कर दी थी ६ सड़क उपर उठा दी परंतु दोनों तरफ की ४ वर्ष के बाद भी पट्टियां नहीं भरी गई पेंच वर्क, गड्डे भरने का काम आशापुर से नए हरसद तक अधूरा है। ३ टोल बूथ पर वसूली। (६) बिना लेटर हेड के पूर्णता प्रमाण पत्र क्र. ७३/एमपीआरडीसी/ डीयूबीबी/ ०७-०८/ ६९७२ भोपाल दि.३१/१/०८ देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग ९८.२५८ किमी मैं. आर व्ही. इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनिर्स प्रा.लि. बैंग्लोर को जारी किया गया अनुदान रु. २४.२७ करोड़, स्टोल पर वसूली।(७) पूर्णता प्रमाण पत्र क्र. २८/एमपीआरटीसी/ आर आर/०८-०९/ ७७०५ भोपाल दि. २४/१/०९ रायसेन राहतगढ़ मार्ग १०१.४ किमी एमएस के हाइवेन लि. बडौदा अनुदान रु. ३२.७७ करोड़, २ टोल बूथों पर मार्च ०७ से वसूली शुरु हो गई थी। (८) पू.प्र.क. एमपीआरटीसी/ जेएमपीआरडी/०७/ ६९५ भोपाल दि. ५/५/०७ जबलपुर-नरसिंगपुर-पिपरिया माग्र १४१.३७ कि मै. जेएनपी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रो.प्रा.लि. जलगांव को रु. ४५.८१ करोड़ के अनुदान के साथ स्वीकृत किया गया। २ टोल बुथों पर वसूली। (९) पू.प्र.क. ५३/एमपीआरडीसी/ एचपीपी/ २०१०/ १५५४ भोपाल दि. १८/५/२०१० होशंगाबाद-पिपरिया-पंचमढ़ी १२६.६८किमी यह सड़क भी १५ फुट चौड़ी है चेतक इंटरप्राइजेस प्रा.लि. उदयपुर(राज.)के कुल लागत रु ५९.८८ करोड़ पर ६०प्रतिशत अनुदान रु.३५.४९ करोड़ दिया गया यहां भी वसूली जन ०८ से ही शुरु हो चुकी थी। २ टोल बूथों पर वसूली पत्र क्र.८५२३-२४ दि.२७.३.०८ से ही शुरु हो चुकी थी। पू.प्र. १८/५/१० को जारी हुआ। (१०) पू.प्र.क. ८२/ एमपीआरडीसी/ आरआर/ २००९/ ५७३६ भोपाल दि. २२/१०/०९ सितनी-बालाघाट-गोदिंया मार्ग ११४ किमी एएबी इंफ्रास्ट्रक्चर लि. कोलकत्ता इस पर अनुदान दिया गया रु. ३४.८० करोड़ १५ सड़क पर वसूली मार्च २००६ से ही शुरु हो चुकी थी २ टोल बूथ पर वसूली।

इन सबके विपरीत देवास भोपाल कारोडोर पर वसूली २ वर्ष पूर्व से शुरु हो गई थी, लेबड़-रतलाम-नयागांव-मंदसौर-नीचम पर भी वसूली शुरु हो चुकी है। ऐसे अनेकों सड़के हैं जिन्हें अभी तक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए है पर वसूली शुरु हुए वर्षो बीत गए है। जबकि पूर्णता प्रमाण पत्र की तिथि से दिए गए २५,२५ व ३० वर्ष तक वसूली की जाएगी जबकि बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए वसूली पूर्णतः अवैध है। पर डकैत कार्पोरेशन का भी करोड़ों की हिस्सेदारी और वसूली है।

लेह के बादल फटने में चीनी षड़यंत्र

पेज १ का शेष...

न ही कर्जा करके देश पर छोड़कर गए। जितना इन कांग्रेसी श्वानों ने एक तरफ

देश को हर तरह सेन केवल नोंचा वरन् दूसरी तरफ देश के विकास के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगते रहे और अरबों करोड़ का कर्ज भी लाद चुके है। इन सबके विपरीत एक आम आदमी से लेकर समग्र देश की चारों तरफ से सुरक्षा के नाम पर भी न केवल गंभीर नहीं वरन् इनकी नपुंसकता और निकंमेपन की मिशाल भी पूरी, दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जबकि इन्होंने आतंकवादियों को न केवल पकड़ लिया वरन् पकड़कर उनकी सेवा चाकरी, मुर्गमुस्ल्लम, बिरयानी, देश की सुंदरियां भी परोसते रहे।

जिसका सीधा सा उदाहरण काश्मीर के चरारे शरीफ से लेकर, संसद के हमले के षड़यंत्रकारी अफजल गुरु से लेकर अजमल कसाब के बारे में देखा जा सकता है। जिन्हें ये कांग्रेसी अपना दामाद बनाकर न केवल पाल रहे है। वरन् दुनिया को अपनी नपुंसक और निकंमी मानसिकता का परिचय भी दे रहे है। इसके परिणाम स्वरुप हमारे पड़ोसी शत्रु चीन और पाकिस्तान के साथ नेपाल, बांग्लादेश जैसे देश की अब हमारी सुनने की ता दूर कई बार हम को ही आंखे दिखाते है। जिसके लिए ज्यादा दूर नहीं पिछले १० वर्ष का इतिहास गवाह है कि नेपाल अभी ३-४ वर्ष पूर्व ही कोसी नदी का पानी छोड़ बिहार में बाद का तांडव किया था। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की आई एसआई न केवल खिलाना बन चुका है वरन् चटगांव की पहाड़ियों पर आतंकवादी कैंप चला रहा है वह वहां से असम और नेपाल के माध्यम से बांग्लादेश की सीमा के माध्यम पश्चिमी भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाता ही रहता है। इस संबंध में प्रभात झा का ये कथन की बीएसएफ और सीआरपीएफ के सीमावर्ती ९०प्रतिशत अधिकारी तस्करी में लिप्त है कहीं से भी गलत नहीं था वो खुलकर देशी विदेशी मुद्राएं स्वीकार कर पिछले ३०-४० वर्षो से तस्करी करवा रहे है। से लेकर भारत की लेह से लेकर भ्यांभार की सीमा जो चीनी सीमा से लगी है। पर चीन पिछले ६० वर्षों से तांडव करप रहा है वरन् ५०-५० किमी तक न केवल अंदर घुस गया है वरन् सभी प्रकार के षड़यंत्र कर रहा है।

लेह से सटी सीमा में उसने सन् २००२ से बड़े-बड़े विशाल खड्डे बनवाए और उनमें बर्फ जमने के लिए छोड़े रखा फिर भरे जून के अंतिम सप्ताह में सन् २००६ में बम फोड़कर बर्फ पिघलाकर पानी बहाया जिसे हिमाचल प्रदेश और उसकी राजधानी में बाढ़ आई यह सब भारतीय थल सेना की जासूस टुकड़ियों ने भारतीय गृह और रक्षा मंत्रालय को सूचित किया पर इन नपुंसक निकंमों के कान पर जूं नहीं रेंगी बाद में बाढ़ के रुप में उसका खमियाजा भुगत कर चुप हो गए। चीन ने इंग्लैंड द्वारा बनाई गई १९१८ की मैक्मोन लाइन को कभी ही माना।

१९५० में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ३८००० वर्ग भील में फैले आवसाई चीन जो भारत का हिस्सा था कब्जा कर लिया था। सन् १९६२ में ६२००० वर्ग मील में उसने युद्ध के माध्यम से हथिया लिया अर्थात १० लाख वर्ग भील को तो आजादी के १२ वर्ष में ही हथिया लिया इसके बाद लद्दाख भ्यांभार तक फैली लगभग २५००किमी लंबी सीमा में ५०-५० किमी तक उसकी सैन्य और नागरिक गतिविधियां उकसाने और हथियाने के हिसाब से कर रहा है। जब भारतीय राजनीति विदेश रक्षा और गृह मंत्रालय पिछले ५०-६० वर्षो से अपनी नपुंसक, निकंमी मानसीकता का परिचय दे रहा है तो वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे है वरन् अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना ही हिस्सा मानकर पिछले ३० वर्षों से वहां के नागरिकों को चीन आने जाने की खुली छूट देता है।

लेह में ५-०६ अगस्त को बादल फटने की जो घटना घटी उसे वहां के वैज्ञानिक जो मौसम देखते है। आश्चर्य चकित है कि वहां जब पर्याप्त वर्षा नहीं होती और वर्षा के अमाल में हिमालय का वह हिस्सा सूखे के कारणे रेगिस्तान कहलाता है। फिर यदि बादल प्राकृतिक रुप से फटता तो उसका असर व्यापक होना चाहिए था। वहां पर वह भी नहीं हुआ। इसके विपरीत लेह के घनी आबादी वाले इलाके के एक निश्चित भाग पर ही भयानक अचानक १५-२० मिनिट में ही सब कुछ हो गया जबकि इसके पूर्व भी मौसम साफ था और उसके कुछ घंटों बाद भी मौसम साफ था। जबकि ऐसा ही दूसरा हादसा फिर घनी आबादी में अगस्त के तीसरे सप्ताह बाद भी हुआ।

बेशक चीन ने मौसमी बम का इस्तेमाल किया ताकि भविष्य में वो सैन्य ठिकानों पर बारिश कर सारी व्यवस्थाए चौपट कर सके। अभी भी उसकी नियत यह थी कि लेह के इलाके को नष्ट करके निर्जनता का फायदा उठा कर कब्जा कर सके और वहां अपनी चौकियां स्थापित कर सके ८ अग.१० को प्र.मं. मनमोहन ने वहां पहुंचकर रु.१२५ करोड़ की सहायता राशि देकर वास्तविकताओं से पल्ला झाड़ लिया। पर यह निकंपामपन भविष्य में बहुत घातक होगा। अब वह यही कांड चीन से लगी सीमा के हर भारतीय शहर पर बरसाएगा।चीन एक तरफ बंगाल, उड़ीसा झारखंड से लेकर आंध्रप्रदेश के माओवादियों को सभी तरह की जिस में नैतिक, सामारक आर्थिक सहायता देकर अंदर से सुरक्षा को खोखला कर रहा है। तो दूसरी चीन से पाकिस्तान तक रेल्वे लाइन और सड़क बनाकर के माध्यम से गुजरात से लेकर पाकिस्तान से सटी सीमा पर सड़क व रेल लाइन तैयार करने में पाकिस्तान को लगातार सहायता देकर पश्चिम से पूर्वोत्तर तक भारत के विरुद्ध सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने में लगा है।

वहीं भारतीय साइटों पर भी चीनी आक्रमण, डाटा चोरी की शिकयतें न केवल बढ़ रही है वरन भारत में कार्यरत चीनी संस्थान केवल नहीं ज्यादा पैर फैला रहे है जहां भारत के सैन्य संस्थान या सेना के बैरकस, जल सेना और वायुसेना के संस्थनों पर भी वह लगातार उपग्रहों से बारीक नजर रख रहा है। परंतु कांग्रेसी डकैत कमीशन के लिए विदेशों से ही समय बाधित पर डुब्बियां, लड़ाकूविमान, जहाज आदिल रे है पर देश में कुछ मिसाइलें विकसित करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहे है। सेना में जल, थल, वायुसेना तीनों में ही न केवल अधिकारियों, विमान चालकों तक की भारी कमी है। इसकी तरफ रक्षा मंत्रलय का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जिसका फायदा चीन और पाकिस्तान केवल भरपूर उठा रहे है वरन् भारतीय सत्ताधीशों की

साप्ताहिक समय माया

लोकसभा में विदेशी हथियार निर्माताओं के बाजार की वकालत

राष्ट्र में छोटे आग्नेय अस्त्रों की बाढ़ की तैयारी

गृहमंत्री पी चीट अंबर लोकसभा में पैरवी कर रहे लाइसेंस युक्त शस्त्रों की

पूरे देश में गृहमंत्री रहते हुए पी चीट अंबर ने पुलिसियों की जानबुझकर नक्सलियों के हाथ मरवाकर आदिवासियों को नक्सलियों के नाम मराने का नया हथिया प्रयोग करना शुरु कर दिया। इसकी आड़ में चीट अंबर जोकि पेशे से विधि सलाहकार है। विदेशी छोटे अथियार निर्माताओं की पैरवी कर राष्ट्र की जनता को उसकी सुरक्षा के लिए हथियार रखने के लिए लाइसेंस मुक्त करवाना चाहते है। जिससे हथियारों को खरीदने और रखने में जनता को राज्य सरकारों से लाइसेंस के लिए परेशान नहीं होना पड़े।

वर्तमान में भारत में शासकीय स्तर पर शस्त्र रखने के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रु.५००००/- तक खर्च करना पड़ते है। जिसमें लाइसेंस की फीस के अतिरिक्त रु.२००००/- एसडीएम रु.१००००/- संबंधित थाने के थानेदार के सत्यापन, रु.५०००/- फाइल बनाने वाले बाबु के रु.५०००/- लाइसेंस देने के समय, अर्थात जहां-जहां से फाइल गुजरेगी जिलाधीश से एसपी आफिस फिर वहां से संबंधित थाना सत्यापन फिर सब कुछ ठ्ठीक ठ्ठाक रहा तो फिर राज्य के गृहमंत्रालय तक फाइल आने जाने में उसे ६महीने का समय लगना मामूली सी बात है। बेशक जिसकी नीचे से उपर तक पहुंच है। रूतबे वाले शक्ति संपन्न नेता मंत्री या शासकीय स्तर के अधिकारी आदि के चलते १ महिने के समय में लाइसेंस मिल पाता है। इन सबसे बचने के या इतनी उलझनों के चलते लाइसेंस की प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहता।

इस सबसे मुक्ति दिलाने के लिए केन्द्र के गृह मंत्रालय के गृहमंत्री पी चीट अंबर की तैयारी थी कि आम आदमी को उसकी सुरक्षा की आड़ में लाइसेंस मुक्ति हथियारों की व्यवस्था के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाए। जबकि विदेशी हथियार निर्माताओं ने जैसे ही कांग्रेस ने सत्ता संभाली और चीट अंबर को गृह मंत्रालय का आबंटन हुआ इस को न केवल अपना सलाहकर नियुक्त कर संभवतः रु.१०००/- करोड़ की चढ़ोत्री, अमेरिकी डालर में २० करोड़ डालर विदेशी खाते में जमा करवा दिए और प्रति रिवाल्वर, पिस्टल,२०० अमेरिकी डालर का कमीशन जो रु.१००००/- होता है का वादा कर दिया गया या सौदेबाजी की गई। फिर क्या था सलाहकार महोदय ने लोकसभा से ही शुरुआत की क्योंकि वर्तमान में भारत में लगभग १२ से १५ करोड़ कारे है। यदि सभी कार वालों को ही उनकी सुरक्षा के नाम पर भी एक-एक पिस्टल रिवाल्वर बेंची गई जिसकी कीमत मात्र १लाख से २ लाख होगी। जबकि वास्तविक कीमत मात्र रु.५००/-अर्थात रु. १०००/- यदि विज्ञापन प्रचार और दहशत फैलाने में भी खर्च किए गए तो सब कुछ जिसमें कमीशन, आदि का खर्च रु. २५०००/- तक भी आया तो रु.७५०००/- प्रति रिवाल्वर फायदा विदेशी कंपनियों को होगा।

वह बात दूसरी है, कि फिर चीनी और देशी कट्टे रिवाल्वरों से भारत के बाजार भर जाएंगे जो मात्र रु.१००० से २००० में ही बेंचना शुरु कर देंगे। जिससे भारत के १० करोड़ से ज्यादा करोड़ पतियों की बिगड़ैली औलादों के लिए यह अमीरी दिखाने और शान बधारने के लिए स्कूलों और कालेजों में बात-बात पर रिवाल्वर दिखाने, चलाने, घायल करने और निपटा देने के कांडों की बाढ़ आ जाएगी। दूसरी तरफ युवा पीढ़ी जो बेरोजगार घूम रही है। उसे अपराध करने और लूट-पाट करने वसूली करने, धमकाने चमकाने का आसान व्यवसाय मिल जाएगा। बेशक फिर घर से निकलकर, शाम को पुनः सुरक्षित घर पहुंच जाना भी एक अजूबा बन जाएगा। फिर नक्सलियों को हथियार लूटने की बड़ी योजनाए नहीं बनानी पड़ेगी। फिर सरकारी अधिकारियों से काम लेने के लिए धन की नहीं रिवाल्वर दिखाकर ही काम चल जाया करेगा। इसके विपरीत नेताओं, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की वसूलियों, रिश्वत खोरी, न सुनने की आदतों के चलते हर शहर में एक दो टपकाने की घटनाए शुरु हो जाएंगी तो केन्द्र और राज्य सरकारों को हर वर्ष भर्ती करना पड़ेगी। तो रोजगार बढ़ेगा, फिर बिरले ही सरकारी अधिकारी, कर्मचारी सेवा निवृत्ति अपने समकक्ष, कनिष्ठ या वरिष्ठ से स्वार्थो के चलते कहीं न कहीं तो नोंकझोंक होगी ही उससे बच गए तो फिर जनता से नोंकझोंक में कहीं न कहीं ये पिस्टल रिवाल्वर चलेगी ही तो २-५-१० बार घायल होंगे कभी तो उल्टी सीधी गोली लगकर मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ेगा।

बिहारी लालू यादव ने चीट अंबर के इस प्रस्ताव का न केवल विरोध किया वरन् सिरे से खारिज करवाने की कोशिश भी की। इसके विपरीत चीट अंबर अपने गृह मंत्री होने का फायदा उङ्गाकर फिर सलाहकार ने जो २० करोड़ डालर की फीस ली है। कहीं तो चुकाना ही पड़ेगा गाहे बगाहे कांग्रेस के शासन काल में छोटे हथियारों को लाइंसेंस मुक्त करने की लगातार पहल की जाएगी। इसके लिए बाकायदा सारे समाचार पत्रों में आपराधिक खबरों को छापने जो आम आदमी में भारी दहशत और खौफ पैदा करें। टीवी समाचार शृंखलाओं को जोड़कर पूरा आपराधिकता से भरे समाचारों का अभियान चलाने की शुरुआत की जा चुकी है। फिर भारत में करों, जहाजों को रखने की होड़ मची है तो हथियार कैसे और क्यों पीछे रहें। अब न केवल पुरुष वरन बड़ी संख्या में महिलाएं भी हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस मांग रही है। अभी रईसजादियां कारे चलाकर नशें में लोगों को कुचल कर मार रहीं है। फिर रईसजादियां अपने सुख सुविधा, अय्यासी में खलल पड़ते ही पति, सास, ससुर और बच्चों को भी गोलियां मारने से नहीं चुकेगीं। चाहिए यह क्रांति भी इस देश को चाहिए। आखिर कमीशन खारे डकैत कांग्रेसी सत्ताधीश सब जानवर भी स्वयं ही इस बहाने अपनी मौत का दावत देने से नहीं चूकने वालें।

भारत में जांच एजेंसियों की नौटंकी

पेज ८ का शेष...

फंसाकर खुद निकल लेते है।फिर वर्तमान में सीबीआई तो शुद्धतः कांग्रेस ब्युरो ऑफ इनवेस्टीगेशन बन चुकी है। जैसे कांग्रेस चाहती है ब्यूरों वैसे ही काम करता है। अभी जब परमाणु समझौते पर कांग्रेस को भाजपा का साथ चाहिए था, तो उसने खुल कर सौदेबाजों की। जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सीबीआई बार-बार जांच के लिए परेशन करती थी। अचानक उसी मोदी का क्लीन चीट दे दी और सोहराबुद्दीन ही इतिहास की गर्त में सीबीआई ने अपने आका के इशारे पर दफन कर दिया।

महाराष्ट्र के एटीएस ने हिन्दु साध्वियों को गिरफ्तार कर उनका मुंह बंद करने के लिए यौन-प्रताड़नाए दी। वहीं हाल कर्नल पुरोहित का किया क्योंकि वहां भी कांग्रेस की सरकार है। मुस्लिम परस्त कांग्रेस अपने मुस्लिम वाटों के लिए अफतल गुरु, अजमल कसाब, जिन्हें फांसी की सजा दे देनी चाहिए थी। उनके चरण पखार प्रथम श्रेणी का नागरिक मान उन पर करोड़ों रुपया खर्च करती है।

वहां से लेकर राज्यों के लोकायुक्त पुलिस संगठनों में भी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बैठाकर, जिन्होंने जीवन भर सत्ताधीशों और पूंजीपतियों के लिए आम जनता को शब्दों के माया जाल में उलझा कर फैसले दिए जिसमें आम नागरिक का भरपूर शोषण हुआ वहीं हाल आर्थिक अंतेषण ब्यूरों का भी हो। दोनोंही संगठन के वहीं पुराने पुलिस विभाग के जालसाज, धुर्त पुलिसिए बैठे है जिनका एक मात्र काम है। कि जांचे और ठ्ठोस निष्कर्स निकलें न निकले अपराधी को सजा हो न हो। उसके विरुद्ध चल रहे प्रकरणों में केवल जांच के नाम पर खुलकर वसूली करों। हाथ पोछों और चल दो। हालात यह है, कि भ्रष्ट विभागों ने अपने विरुद्ध कोई ठ्ठोस कार्यवाही न हो इसलिए स्वयं ही पूरे प्रदेश से पैसा पहुंचाना शुरु कर दिया। जिसमें वाणिज्य कर, आरटीओ, एक्साइज, संपत्ति क्रय विक्रय पंजयिक लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन महिलाबाल विकास आदिमजाति कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगमों आदि से करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के हर महीने पहुंचा दिए जाते है। इसलिए सैंकड़ों शिकायतें होने के बाद भी जांचों को पंजीकृत नहीं किया जाता और वसूली शुरु हो जाती है। दूसरा इन हरामखोरों की सतर्कता समीतियों में बैठे अपने आप को न केवल खुदा समझते है वरन् धन का लेन-देन कर १५ से २५ वर्षों तक जांचों को खींचकर उलझाए रखा जाता है। आखिर बैठे तो यहां भी सभी भुखेरे श्वानों की फौज ही है। जिसे काम से नहीं। वरन् अपराधी से वसूली से मतलब होता है।

दूसरी ओर लोकायुक्त और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरों की बिडंबना यह है, कि न तो इनके पास पर्याप्त स्टाफ होताहै, न साधन, न अच्छे गंभीर अध्ययनशील और मेहनत कश वकील। ताकि शीघ्र और ठ्ठोस निर्णय ले सके। दोनों ही संगठन होते ही है सत्ताधीशों और पूंजीपतियों की कठपुतली है। जिन्हें सत्ता के इशारे पर ही नाचना पड़ता है।

५-६-७ अगस्त १० को लोकायुक्त नान लेकर व इनकी टीम इंदौर में भी जांच की नौटंकी करने शासकीय स्तर पर आई थी। एक दिन जनता और पत्रकरों को भी उस टीम की जन संपर्क अधिकारी या लोकायुक्त की निजीसचिव की हैसियत से श्रीमती कोल जनता व पत्रकारों से बातचीत की, क्षेत्रीय पत्रकारों जो दैनिक समाचारों ने जो प्रश्न पूछे। उनमें थे। कितनी शिकायतें आई। कोल का जवान था ३२ किस-२ की आई। तो श्रीमती कौल ने बताया कालोनीवालों की आई, अवैध कब्जों की आई। अब देखने वाली बात यह थी,कि जब वो लोकायुक्त जैसे संगठन की प्रवक्ता बन कर जवाब दे रही थी तो क्या ये जवाब देना चाहिए था कि किस-२ की आई। जब तत्काल शिकायतों पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित था। इस प्रतिक्रिया चाहे शिकायत कर्त्ताओं की जिंदगी ही खबरे में पड़जाए। दूसरा शिकायतें खोजबीन के बाद ही सत्य और ठ्ठोस सबूतों के आधार पर शिकायतें मानी जाएंगी इसके विपरीत छपास रोग के चलते ऐसे प्रश्नों के भी जवाब दिए गए ताकि मिडिया में नाम आ सके।

समय माया की तरफ से श्री अजमेरा भी उपस्थित थे, तो जब उन्होंने सभी पत्रकारों के बीच में पूछने की कोशिश की वो दैनिकों के पत्रकार गुर्राए और बौले आप कौन। जबकि अधिकांश पिछले १० वर्ष से जान रहे है। उन्होंने बड़े शांत भाव से भाई मैं समय माया का मुख्य संपादक, तो फिर गुर्राए बोले, नहीं आप नहीं पुछेंगे। हम डेली(उल्टी सीधी आधार हीन, जनता को भ्रमित करने वाले समाचारों की उल्टी-पलटी) वाले है हम पूछेंगे। श्री अजमेरा कौन मुंह लगे और सबका समय बर्बाद करें चुप रहे। जब सब उपरोक्तानुसार सवाल पूछ कर हटे। हटते ही साथ श्री अजमेरा का श्रीमती कौल से पहला प्रश्न था कि आप बताए कि पिछले २७ वर्षों में आपने कितने भ्रष्टमंत्रियों और अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किए और कितनों को आपकी कार्रवाहियों से सजा हुई। ये पूछते ही श्रीमती कौल का जो चेहरा दैनिक वालों से बाते करते हुआ मुस्करा रहा था। एकदम कुम्हला गया और बोली नहीं-नहीं ये मुझे पता नहीं है। ये तो आप लोकायुक्त से ही पूछिए। श्री अजमेरा ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि चलिए बता दीजिए कि कुल कितने प्रकरण जांच में है। जिनकी ५ से १५ वर्षों से केवल जांचे ही चल रही है। कितनों के चालान न्यायालय में पेश कर दिए और न्यायालयों में लंबित है। अब श्रीमती कौल का चेहरा देखने लायक था। चेहरे पर खीझ छुपाते हुए बोली, कि आप सब लिखकर दे दीजिए। जवाब मुख्यालय से भिजवा देंगे। फिर अजमेराजी बोले चलिए इसे भी छोड़िए। तीसरा अंतिम प्रश्न बता दीजिए कि मुख्य अभियंता डामोर एकपीपीएचई इंदौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशुतोष अवस्थी इंदौर और तीसरे रघुवंशी तीनों ने उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच में ३ वर्षों से विभागीय जांच के प्रकरणों पर स्थगनले रखा है। वर्ष में दो-तीन पेशियां पड़ती भी है। तो एक न्यायाधीश तीनों को एक साथा सुनने की प्रक्रिया चलाते है। दूसरे तीनों को दूसरी पेशी में अलग-अलग सुनने की बात करते है। यदि विभागीय जांच पर स्थगन है। तो आप न्यायालय में चालान पेश करने की पात्रता का उपयोग कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत क्यों नीं कर रहे। तो जवाब था कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये भी आप लोकायुक्त साहब से ही पूछे।

निष्कर्ष यह है कि केन्द्र से लेकर राज्यों की सभी जांच एजेंसियां सत्ताधीशों और पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली कानूनी नौंटकियो की ऐंसियां है। जो पूंजीपतियों और सत्ताधीशों के इशारे पर सारी जांच का नाटक करती है। धन व शक्ति संपन्न से धन कमाकर निरीहों का शोषण करती है। चाहे वो एटीएस हो,सीबीआई, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यु या कोई भी आयोग, समीति आदि हो इनसे न्याय की उम्मीद, खंभे पर टंगी बीखल की खिचड़ी की हांडी है।

जातिगत ही हो जनगणना

पेज १ का शेष...

कांग्रेसी गिरोह उस मंत्र का अक्षरश पालन कर रहा है। इसके लिए ५० वर्ष तक उन्होंने इसी दम पर राज किया हिन्दु मुस्लिम दंगे करवाना फिर हिन्दुओं को प्रताड़ित करना और मुस्लिमों का अधसहयोग करना यही कारण था कि अफजल गुरु को फांसी की सजा दिए जाने के बाद भी ये धूर्त शूकरों की फौज केन्द्रीय गृह और विधि मंत्रालय से दिल्लीराज के गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय में ही उस फाइल को ३ वर्ष से ज्यादा समय से दौड़ा-दौड़ा कर समय पूरा कर अफजल गुरु की फांसी मुस्लिमों के वोटों के लिए टाल रही है। जिसने इस राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता के केन्द्र संसद को उड़ाने की कोशिश की थी।

अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के साथ मौलिक हथियार के रुप में जो गुरु मंत्र दिया फूट डालो राज करो, हमने ३०० वर्ष किया का ही मूल चरित्र कांग्रेसियों ने ६० वर्ष से ओढ़कर पहले हिन्दु मुस्लिम दंगों से सत्ता हथियाई, जब ये हथियार मोथरा पड़ने लगा तो इंदिरा गांधी ने रणलिस्तान और मुस्लिम आतंक को हथियार बनाया। जो स्वयं इंदिरा की हत्या कारण बन गया। नेहरु के स्वतंत्र काश्मीर और मुस्लिम आतंक को पाला पोसा। जो अभी तक भारत में नासूर की तरह बट रहा है। फिर मुस्लिमों को सहयोग करना आतंकी कार्रवाईयां विस्फोट करवाना। फिर पकड़े जाने पर उन्हें बचाना। हिन्दु साधु, संतों, साधियों को आतंकी घोषित करना। पुलिस अमिरथा में उनका अनेकों पुलिसियों शरीरिक-मानसिक शोषण करना और प्रताड़ना देना। ये कांग्रेसी गिरोह के सारे हथकंडे जातिगत ही है। तो जनगणना जातिगत क्यों नहीं की जाएगी।

इन सबके विपरीत जातिगत जनगणना के वैज्ञानिक पहलू भी सैंकड़ों है। जातिगत जनगणना से स्वयं शासन तंत्र को ये मालूम पड़ सकेगा। कि शिक्षा के नाम पर जो अरबों रु. पिछले ३०-४० वर्षों से बहाया जा रहा है। उसका किस जाति पर कितना असर हुआ। परिवार नियोन व जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किस जाति पर कितने सफल हुए। वास्तविकता में कहां ध्यान देने की जरुरत है। अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर औसतन केन्द्र सरकार विभिन्न मदों से रु.१से डेढ़ लाख करोड़ खर्च कर रही है उसकी वास्तविकता क्या है? क्या सचमूच ६० वर्षों से ज्यादा समय से खर्च की जा रही ये रकम कहां खर्च हो रही। अन्यथा ही खर्च हो रही है। तो फिर क्यों अभी तक उस पर ध्यान देकर उसमें परिवर्तन लाए जा रहे। आम मध्यमवर्गीय सामान्य हिन्दुओं के मुंह से ही क्यों निवाला छीना जा रहा है। उनके गरीब प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को क्यों छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। क्यों उनके आगे सामान्य वर्ग को हर कदम अभिषाय बना कर प्रस्तुत किया जाता है। प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों से लेकर सरकारी नौकरियों में, फिर पदोन्नतियों। जातिगत जनगणना से ये आंकलन करने में मदद भी मिलेगी कि आर्थिक समृद्धि के लिए जातिगत आधार पर कहां किसे कितना सहयोग सरकार को देना चाहिए।

जब जातिगत आधार पर सच्चा कमीशन पिछले बीस वर्ष से ज्यादा समय से चला आ रहा है। जबकि सच अधिकांश कमीशन, पांच आयोग, अपने कार्यो को अपनी तरह से, कमीशन देकर, इच्छानुसार जांच रिपोर्टस तैयार की जाती है।

दूसरी तरफ जातिगत आरक्षण देकर उन जाति विशेष के ०.५प्रतिशत लोगों का ही फायदा हुआ जो सरकारी नौकरियों में थे उसके बदले वास्तविक राष्ट्र को कितनी हानि वर्तमान में हो चुकी है और भविष्य में नासूर बन कर कब तक बहेगी।

पिछले ३० वर्षों में कांग्रेसी गिरोह का मुस्लिम अनुसूचित जाति जनजाति का वोट बैंक उसके हाथ से खिसक चुका है। सन् २००४ का चुनाव कांग्रेसी गिरोह न भाजपाई प्रमोद महाजन की नासमझी और लालच से और २००९का चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की जालसाजी से जीता है। जिसे सर्वोच्च न्यायालय तक में खींचा जा चुका है। अमेरिका के साथ पूरा युरोप भी भारत के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की जालसाजी ही मानता है। जिसकी सच्चाई समय माया ने मार्च २००९ में ही चुनाव आयुक्त चावला की नियुक्ति के साथ ही घोषित कर दिया था। यह कांग्रेस भी जानती है।

अर्थात जातिगत जनगणना करवाने के सैकड़ों आधार है। जो भविष्य में भारी उपयोगी सिद्ध होंगे। फिर आजादी के बाद से अभी तक सारी राजनीति, वोट, चुनावी समीकरण, विकास की अवधारणा, सब जातिगत है। तो जनगणना में जाति न डालकर स्वयं सभी अपने आप से छलकर रहे है।

आवेदकों, अपीलाटंस को मानसिक प्रताड़ना

म.प्र.सूचना आयोग-जालसाज आयुक्तों का अड्डा

किसी भी आईएएस व धन बांटने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं

मि.अजमेरा हम मंत्री, विधायक, उपर के अपने वरिष्ठ अधिकारियों, पत्रकारों जैसे 15 कुत्तों को रोटियां डालते है, एक सूचना आयोग जैसे 16 वॉ और सही, उसे भी टुकड़े डालेंगे वो भी हमारे पक्ष में ही फैसला देगा, पीएलई सेवा निवृत्त का अ. जगदीश भाटिया का यह वक्तव्य जो सूचना अधि. अधि.05 के लागू होने और आयोग के गठन पर उक्त इंजिनियर ने दिया था, एकदम सच था, जिसे यहां बैठे धूर्त जालसाज मु.सू. आयुक्त पीपी तिवारी, सू.आ. आजमगढ़िया जालसाज आयुक्त इकबाल अहमदं, पुलिस विभाग का धूर्त जिसे पत्रकारों ने डकैत संहारक का नाम देकर महान बनाया था, जबकि पुलिस सूत्रों के अनुसार ही इसने कभी कोई डकैत और अपराधी नहीं मारा वरन जिस पुलिस वाले ने डकैत मारा था डले ही उसे दिनेश जुमरान ने मारा बताने के लिए पुलिस वाले को ही निपटा दिया गया, जिसे अपने पूर्व के कुकमों से इतनी दहश रहती है, कि आयोग के कार्यालय में भी आते-आते समय भी रोब झाड़ने और सुरक्षा के लिए अभी भी आदमी रखना पड़ते है।

दिनेश जुगरान भी सूचना आयुक्त है। इन तीनों हरामखोरों का इस आयोग में बैठकर शासन की सुख-सुविधाओं का लाभ लेना, सेवानिवृत्ति के बाद भी पूरा वेतन भत्ते, बंगला, लालबत्ती आदि का भरपूर वेतन लेते हुए अपील कर्त्ताओं को ही ये तीनों हरामखोर मानसिक प्रताड़ना देकर अधिकारियों को बचा रहे है।

ये हरामखोर तीनों आयुक्त, पिछले 5 वर्षो में 5 व्यक्तियों को भी रु. 25000/- का दंड तो दिया ही नहीं गया साथ ही आवेदक को कानून में व्यवस्था होने पर भी उसे कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं दिलवाई गई,इन भ्रष्ट शूकरों की जालसाजियों में आयुक्तों के साथ वहां पर बैठ स्टॉफ भी महामक्कार, निकंमा और इतना बदत्तमीज है, कि उनसे पूछताछ करेन पर ये अपनीलांटस पर तो एक तरफ फूफकारते है, जबकि दूसरी ओर सरकार अधिकारियों के आगे पीछे घूमते है।फिर पूरा आयोग सरकारी भ्रष्टतंत्र का हिस्सा बन गया है। इसका अंदाज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस आयोग प्रदेश के 50 जिलाधीशों और उसके अंतर्गत कार्य करने वाले 90 से 105 विभागों में सभी संभागायुक्तों से अपने संभागों की धारा 4 की जिसमें 17 बिंदुओं की जानकारी इंटरनेट साइडों पर डाली जानी चाहिए थी 5 वर्ष बाद भी डलवाने की तो दूर वरन जिन्होंने जिसमें जिलाधीश देवास भी थे इन हरामखोरों न जानकारी डालने के कारण उन्हें पत्र देकर हतोहित ही किया। यदि धारा 4 की जानकार डाल दी जाती तो इन हरामखोरों शतानों की फौज पूछ-परख की समाप्त हो जाती।

इस अधिनियम की जो पारदर्शिता की मंशा थी उस आयोग में घोर भ्रष्ट और निकंमें ही बैच दिए गए तो कैसे उम्मीद की जा सकती है, कि ये शासन को कहें कि कम से कम चारा 4 जानकारियां डाले,

जिलाधीश जिले का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है, सारि योजनाओं का धन वितरण करने कार्योक पर नियंत्रण रखने, हर सप्ताह सभी अधिकारियों की सभा बुलाने व शासकीय कार्यो को संपन्न करवाने के लिए जिम्मेदार होता है केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उसके जिलाधीश कार्यालय में ही होता है जिसे धारा 4 की जानकारी जिले की साइट पर डालना और समयानुसार अपकृत करना चाहिए। श्री अजमेरा ने देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, शाजापुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर आदि जिलों में सूचना के अधिकार में धारा 4 के अंतर्गत जिलाधिशों को हर वर्ष में जानने के लिए पत्र दिए, तो जिलाधीशों ने जानकारी डालना शुरु भी की थी, पत्रों का जवाब संतोषजनक न पाए जाने और जानकारियां न मिलने क दशा में प्रथम व द्वितीय अपीले की इस सूचना आयोग ने श्री अजमेरा की अपीलें खारीज करना दी, इनकी बतमीजीयों का ये उत्कृष्ट नमूना है ये इन पत्रों की प्रतियां संल्गन है।

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
क्र.ए-0436/रासूआ/38-06/ इंदौर/2008/3693 भोपाल दिनांक 31/03/2010

प्रति,
श्री अजमेरा एस.पी. कुमार,
299, अम्बेडकर नगर,
इंदौर

विषयः- द्वितीय अपील क्रमांक ए-0436 श्री अजमेरा एस.पी.कुमार, इंदौर विरुद्ध लोक सूचना अधिकार, कार्यालय कलेक्टर, बुरहानपुर

संदर्भः- 1.आपका अपील आवेदन दिनांक 04/02/2010

आपके द्वारा आयोग को प्रस्तुत द्वितीय अपील क्रमांक ए-0436 में आपने लोक सूचना अधिकारी काय्रालय जिलाध्यक्ष बुरहानपुर को प्रस्तुत आवेदन दिनांक29.1.09 को प्रस्तुत कर विभिन्न विभागों से वांछित जानकारी चाही थी।चूंकि इन सभी विभागों में शासन द्वारा पृथक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है अतः आपको परामर्श दिया जाता है कि प्रथक लोक सूचना अधिकारी के लिए पृथक पृथक आवेदन एवं उसके लिए पृथक प्रथम अपील प्रस्तुत करे। अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय से अनसन्तुष्ट होने पर पृथक आवेदन एवं अपील हेतु पृथक पृथक द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत कर सकते है।

इस परामर्श के साथ ही आपका अपील प्रकरण क्रमांक ए-0436 आयोग स्तर पर नस्तिबद्ध किया जाता है।

(प्रकाश खरे),उप सचिव
राज्य सूचना आयोग

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
क्र.ए-0437/रासूआ/38-06/ इंदौर/08/381 भोपाल, दिनांक 01/3/10

प्रति,
श्री अजमेरा एस.पी. कुमार,
299, अम्बेडकर नगर,
इंदौर

विषयः-अपील क्रमांक ए-0437 श्री अजमेरा एसप कुमार, इंदौर विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, खंडवा मध्यप्रदेश।

संदर्भः-1. आपका आवेदन दिनांक 20.2.2009 के संबंध में।

आपके द्वारा आयोग को प्रस्तुत द्वितीय अपील क्रमांक ए-0437 के संबंध में अवगत होवें कि आपने दिनांक 16.12.08 को लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, खंडवा को आवेदन प्रस्तुत की भिन्न-भिन्न विभागों से संबंधित जानकारी चाही है। कृपया इस संबंध में अवगत होवें कि भिन्न-भिन्न विभागों के संबंध में पृथक-पृथक लोक सूचना अधिकारी पदस्थ है। अतः आपको परामर्श दिया जाता है कि आप पृथक-पृथक ग्राम विभागों के संबंधित जानकारी चाहने के लिए पृथक-पृथक संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। लोक सूचना अधिकारियों द्वारा जानकारी उपलब्ध न कराने पर पृथक-पृथक लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध पृथक-पृथक प्रथम अपील एवं अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय से असंतुष्ट होने पृथक-पृथक द्वितीय अपील आयोग को कर सकते है इस परामर्श के साथ ही आपकी द्वितीय अपील क्र.ए-0437 आयोग स्तर पर नस्तीबद्ध की गई है।

(प्रकाश खरे),उप सचिव
राज्य सूचना आयोग

देवास जिलाधीश के विरुद्ध 15/4/08 को आदेश पारित होने से देवास जिलाधीश ने अधिकांश विभागों की जानकारी न केवल उस पर डाली वरन इस कारण आयोग को देवास के विभागों से अपीले मिलना ही लगभग बंद हो गई, इससे आयोग में बैच सू.आ. इकबाल अहमद बोखला गया क्योंकि उसकी कमाई पर भी असर पड़ा।

इन निकंमे शतानों का अपीलायंस को प्रताडित करने का एक अंदाज और भी है, पत्र प्राप्ति के दो तीन महीने बाद भ्रष्ट अधिकारी जो इन्हें पेंट पूजा देता है जिसमें वाणिज्य कर विभाग इन हरामखोरों की महीना मिलता है इसलिए अधिकांश अपीले ये शब्दों के मायाजाल में उलझाकर खारिज कर देते है। इसका एक नमूने नीचे देखिए।

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
क्र.ए-0424/रासूआ/07-02/ इंदौर/09/3695 भोपाल, दिनांक 31/3/10

प्रति,
श्री अजमेरा एस.पी. कुमार,
299, अम्बेडकर नगर,
इंदौर

विषयः-अपील क्रमांक ए-0424 श्री अजमेरा एसप कुमार, इंदौर विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त,वाणिज्य कर, इंदौर।

संदर्भः-1. आपका अपिल आवेदन दिनांक 25.2.2009 के संबंध में।

आपके अपील आवेदन में निम्नानुसार कमियां हैः-

1.लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 16.12.08 की तीन प्रतियां संलग्न नहीं है।

अतः आपको परामर्श दिया जाता है कि आप उपर्युक्त कमियों की पूर्ति कर आवेदन दिनांक 18.4.2010 तक भेंजे ताकि आपके प्रकरण में कार्यवाही की जा सके।

(प्रकाश खरे)
उप सचिव,
राज्य सूचना आयोग

उपरोक्त पत्र में जानबूझकर प्रतिवादि का नाम पूरा नहीं लिखा गया अकेले इंदौर में वाणिज्य कर के 10 से ज्यादा उपायुक्त बैच्ते है। तीन वाणिज्य कर संग्रह, 3 अपीलेट, 2 एंटी इवेजन ब्यूरों।

अंकेक्षण, और 4 से ज्यादा मुख्यालय में बैच्ते है आद के विरूद्ध अपीले भेजी गई थी, कौन सा उपायुक्त वाणिज्य कर है, उसे बचाने और अपने निकमेपन को छुपाने हरामखोरों ने पूरा और सही पता नहीं लिखा, दुसरा दुसरा जान बुझकर, संबंधित अधिकारी अनावेदक से लेन-देन कर प्रतियां कम होने का शिजूका छोड़ बचालिया गया। अब किसकी फोटो कापी भेजे जाए, करोड़ों रु. का आबंटन उकारने वाले ये शूकरों की फौज के

पास स्वयं की फोटो कापी मशीन है, यदि ईमानदारी होती तो ये लिखने की अपेक्षा इस अपील की फोटो कॉपी करवा कर कार्यवाही संपन्न करते, ये हरामखोर शतानों की फौज बहुत अच्छी तरह से जानती है, कि अगर श्री अजमेरा अपीले भेज रहे है, तो अनावेदक सिर झुकाकर वहां अपील में सुनवाई के लिए पहुंचकर चढ़ोगा भी चढ़ा रहे है।अन्य या देवास में धारा 4 के पालन से अपीले घट कर नमा मात्र रह गई है।

यदि सूचना आयोग में बैच सेवानिव्रत्त आयुक्तों की फौज में थोड़ी सी भी ईमानदारी जनता के धन से मिलने वाले वेतन के प्रति थोड़ी सी वफादारी निभाने क नियत होती तो ये शूकरों की फौज न केवल धारा 4 का पालन 5 वर्षों में हर सरकारी विभाग से करवा चुकी होती, साथ ही जनता के धन से होने वाली भ्रष्टाचार की होली के रंगों का अंदाजा कम से कम 1 प्रतिशत जनता तो लगा ही सकती थी, इसके विपरीत जीवन भर डकैती और जनता के धन से लूट खसोंट करने वाले 3 आयुक्तों की बेशर्मी, बतमीजी और निकंमेपन का आयोग क कार्यशैली उत्क्रष्ट है, शाम 4 शासन की मांड गिरी करने अपीलार्थियों को हत्सोहित और मानसिक प्रताड़ना देकर परेशान करने आर कहने पर ये शूकर इकबाल अहमद कहता है, यहां से भी संतुष्ट नहीं हो तो उच्च न्यायालय में जाओ, वहां से जानकारी निकलवाओ कि सलाह नहीं देता जो स्पष्ट करता है, कि हमने जिंदगी भर भ्रष्टाचार और हरामखोरी की है, मरत दम तक यहीं और यहीं करेंगे।

नर्मदा तृतीय चरण-जनता पर 750 करोड़ का कर्ज

पानी-नेताओं, पूंजीपतियों और सत्ताधीशों को

2 दिन में 20 मिनिट पानी, कल आज और कल भी मिलेगा, जनता को तो

इंदौर। नगर की जिस २५ लाख से ज्यादा की आबादी के पीने के पानी के नाम पर रु.७५० करोड़ का कर्ज एशियन विकास बैंक से लिया गया। उस कर्ज का भुगतान तो जनता करेगी। पर जो नर्मदा के तीसरे चरण का पेय जल इंदौर लाया गया उसका लाभ जनता को नहीं मिला उसे कल भी दो दिन के मात्र २० मिनिट पानी जो आम जनता को मिल रहा था, वह वर्तमान में भी मिल रहा है। और भविष्य में भी मिलेगा। जिनको पानी कल भी नहीं मिल रहा था, उन्हें आज भी नहीं मिल रहा है। इस संबंध में जून के महीने में ५४ और ७४ नं. स्कीम के रहवासियों ने एबी रोड पर जाम भी लगाया था। जब पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि तीसरे चरण का पानी वहां लाया जरूर गया था। परंतु वह पानी वहां के एक नेता की शराब फैक्ट्री में चला गया और हम जस के तस प्यासे बैठे है। ये हाल उन सभी बस्तियों का है। जहां मध्यम निम्न मध्यम वर्गीय और गरीबों की झुग्गियां है।

बेशक इस तृतीय चरण के पानी का बड़ा लाभ नगर निगम के पार्षदों, मंत्रियों, शासकीय अधिकारियों की कालोनियों उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की बस्तियों की कालोनियों उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की बस्तियों का बहुत हुआ जिसमें ८०प्रतिशत लोग पानी का पैसा नगर निगम तक में मासिक बिलों का नहीं भरते है। पर नर्मदा के जल का भरपुर फायदा सभी तरह से ये ही उठाते है। गाड़िया धोते है। कुत्ते नहलाते है। उद्योग चलाते है। पैसे देने के नाम पर अपना रुतबा दिखाते है। या फिर आधा इंची के कनेक्शन पर २ इंजी का कनेक्शन चलाते है।

इस संबंध में नगर निगम के जल प्रदाय करने वाले नर्मदा के कार्यपालन यंत्री धमेन्द्र वर्मा से पूछा गया कि आखिर २७० एमएलडी पानी आ रहा है। कितना जल राजस्व प्राप्त हो रहा है। तो तपाक से बोले १००प्रतिशत जब उनसे पूछा गया कि १८० एनएलडी में कितना आ रहा था और जब २७० में कितना आएगा। तो ढीले पढ़ कर बोला कि ४० प्रतिशत जल राजस्व भी मुश्किल से आ रहा है।

अब आपको बता दे, कि एडीबी और विश्व बैंक से मिलने वाले ॠणों के शेडयुल आफ रेट्स और केन्द्रीय सरकार के कार्य विभागों को जारी होने वाले शेडयुल ऑफ रेटस में ४० प्रतिशत का सीधा अतंर आता है।अर्थात जो पानी की टंकी भारत के केन्द्र सरकार और मप्र सरकार के कार्य विभागों की दरों में २० लाख में बनाई जाती है वही एडीवी और विश्व बैंक के अनुसार भारतीय मुद्रा में और भारतीय दरों पर उनके अनुसार रु.२८ लाख में बनाने का इस्टीमेंट स्वीकृत होता है। ताकि बनाने वाली एजेंसी और बनवाने वाली एजेंसी ४० प्रतिशत का व मार्जिन और १५ से २५ प्रतिशत का व मार्जिन जो इस्टीमेंट बनाते समय अधिकारियों और ठ्ठेकेदार के भ्रष्टाचार के लिए शामिल किया जाता है। यह औसतन होता है जैसे पाइप खरीदी और टंकी निर्माण में १० से १५ प्रतिशत और निर्माण कार्य जैसे पाइपलाइन बिछाने आदि में २५ से ४० प्रतिशत तक का होता है। अर्थात जो काम भारतीय केन्द्र आर राज्य सरकार दरों की अनुसूची के अनुसार रु. ४५० करोड़ में होना था रु. ७५० करोड़ का हुआ वह भी कैसा उसे आए दिन दैनिक समाचार पत्रों में जनता पढ़ ही रही है। यहां की पाइपलाईन फूटी वहां फूटी। फिर इस

एडीबी के ॠण के नर्मदा तृतीय चरण के कार्य को संपन्न करने वाली प्रोजेक्ट इंपली में टेशन युनिट में जितने भी लो.स्वा.यां. के महा प्रबंधक से अन्य सभी इंजिनियर जोपीएचई के महा भ्रष्ट इंदौर संभाग में थे जिसमें अधीक्षण यंत्री प्रभात सांखला, का.अ. धमेन्द्र वर्मा, दीपक रत्नाकर, मोनिका मंडलोई, बघेल, गुरुभेद, इस इकाई के कर्ताधर्ता थे। वही हाल सीवरेज प्रोजेक्ट वह भी रु.४४५ करोड़ का है। वह भी भ्रष्टाचार के इन इंजीनियरों की देखरेख में ही संपन्न हो रहा है। बेशक सांखला की एक मात्र इंजिनियर है जो संभागायुक्त, निगमायुक्त से लेकर पार्षदों, नेताओं, भोपाल में बैठे मंत्रियों के मुंह के साइज का टुकड़ा डालकर नर्मदा का पीने का पानी हो या सीवरेज में बहाने का पानी हो।

पहले ४५० से ५०० फीट लाने और फिर नालियों से बहाने से लेकर जेबों से निकालने और पहुंचानेतक के कार्यो को बनिया बुद्धि से सबका ख्याल रखते हुए संपन्न कर रहे है। गरीबों की आंख से ही इतना पानी बहता है। कि उन्हें पिलाने की जरुरते ही नहीं है। फिर उसे न पानी मिलेगा न वो बहाएगा पर बिल तो उसी को देना पड़ेगा।

सारे सूचना आयोग भ्रष्टों, जालसाजों के अड्डे

अधिकांश कार्यवाहीयां अवैध

केन्द्र व राज्य सरकारों के सूचना आयोग केवल कानूनी औपचारिकताएं राष्ट्र की केन्द्र सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम लागू करने और उसकी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए जो औद्योग का गठन किया और राज्य सरकारों में करवाया। वह मात्र दिखाना बनकर रह गया है इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कि स्वयं केन्द्र सरकार केक विभागों ने इसका कितना पालन किया। इसे लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से केन्द्र सरकार के सभी विभागों आयकर, कसम एंड एक्साइज पोस्ट आफिस रेल्वे, संचार विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों और उनकी शाखाओं, कृषि विभाग, उद्यानिकी, पेंशन एक कार्मिक व जन कष्ट निवारण मंत्रालय, खनिज विभाग, महिला एवं बाल विकास, संसदीय के साथ ही, केन्द्र सरकार के उपक्रमों यथा भारत शूकर भ्रष्ट निकंमा लि. दूरदर्शन राष्ट्रीय खनिज विकास विभाग ओएनजीसी, आई ओसी, बीपीसएल, एचपीसीएल जैसे सैकड़ों उपक्रमों तक ने ५ वर्ष बाद भी इंटरनेट साइटों पर सूचनाएं नहीं डाली। जब एक आवेदक ने कार्मिक विभाग से पूछा, और केन्द्रीय सूचना आयोग से पूछा तो दोनों ने ही अपनी-अपनी जिम्मेदारी से पल्ड़ा झाड़ लिया।

जब इस अधिनियम की धारा का पालन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री काग्रलय से लेकर केन्द्र शासन के सभी विभाग, उपक्रम निगम, नियमन आयोग,५ वर्ष बाद भी नहीं कर पा रहे है। फिर जब सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त से पूछा जाता है। तो वह भ्रष्ट ५ वर्ष बाद आवेदक को जवाब देता है। कि ओ हो यह काम भी हमारा था। जबकि इसी सूचना के अधिकार में ये सारी जानकारी मांगने के चक्कर में ८ व्यक्तियों की जान सूचना न देने वाले अधिकारी, पुलिस गुंडे ले चुके होते है।

वैसे भी केन्द्र और सभी राज्य सरकारों ने इन ५ वर्षों में भरपूर कोशिश की है। शतरंज की बिसात जमाई। और इस कानून की औपचारिकताएं पूरी करने के ऐसे सेवानिवृत्त, उच्च भ्रष्ट लोगों को चुनचुन कर बैठाया है। कि उनका पूरा ध्यान सत्ताधीशों को धन लेकर बचाया जाता रहा है। केन्द्रीय सूचना आयोग में भी सारे चुन-चुन कर सदस्यों को भी न केवल भ्रष्टों को बैठाया गया है वरन् वे सब भी खुलकर हरामखोर आवेदकों को हड़काते उराते और धमकाते हैं। जबकि अनावेदकों से खुलकर लेन-देन कर आयोग के आदेशों की कैसे धज्जियां उड़ाती है। इसकी भी व्यवस्था करत`है।

इंदौर केक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एक डॉक्टर ने दिल्ली स्थित अपने वरिष्ठ कार्यालय से जानकारी मांगी। जानकारी नहीं दी गई, डॉक्टर ने पहली अपील लगाई। संतोषजनक उत्तर नहीं आया। अगले ने सूचना आयोग में अपील की वहां से आदेश हो गया कि आवेदक को जानकारी मूफ्त दी जाए। संबंधित लोक सूचना अधिकारी ने फिर भी जानकारी नहीं दी। फिर शिकायत की गई तो लो सू अ ने रद्दी के पेपर का लिफाफा भेज दिया। अगले ने फिर शिकायत की। ८-९ महीने से ज्यादा हो जाने पर भी उस पर कोई कार्रवाही करने को तैयार नहीं है। आयोग अब आमजन अंदाजा लगा सकता हे कि कैसे ये हरामखोर सूचना अधिकार अधि०५ की केन्द्रीय सूचना आयोग के भ्रष्टों पर धन खर्च करके अनावेदक और सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे है। इसके साथ ही स्वयं केन्द्रीय सूचना आयोग बताए कि उसने स्वयं धारा ४ के एबी के १७ बिंदुओं सी और डी का कितना पालन कर सारी जानकारियां इंटरनेट साइटों पर डी तो स्वयं आयोग भी कटघरे में खड़ा नजर आएगा। दूसरी और धारा १९(८) ब में कितनों को क्षतिपूर्ति दिलवाई गई। कितनों पर १९(८)सी में अर्थदंड अधिरोषित किया अक्टू. ०५ से अभी तक तो मालूम पड़ेगा कि पिछले ५ वर्ष में पूरे भारत में २५-५० से ज्यादा को न तो दंड अधिरोपित किया गया और न ही आवेदक के स्तर पर हुई हानि के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया।

राज्यों में मप्र राज्य सूचना आयोग की ही लें, तो यहां पर भी भ्रष्टों की फौज मुख्यमंत्रियों चाहे वो उमा भारती हो, बाबु गौर हो या शिव चौहान हो।इन सब ने भी सेवा निवृत्त जिन श्वानों की फौज बैठायी उन सब ने दोनों हाथ से माल बटोरा और पिछले ५ वर्षों में किसी भी आवेदक को क्षतिपूर्ति देने की तो दूर, सबने जिसमें मु.सू.आ. पीपी तिवारी से लेकर सू.आ. इकबाल अहमद पुराना भ्रष्ट आईएएस, सू.आ. दिनेश जुगरान सभी अधिकारियों को धन लेकर सभी अधिकारियों न केवल बचाया इन जालसाजों ने आवेदकों को न केवल हतोत्साहित भी किया दूसरी यदि देवास कलेक्टर ने धारा ४ का पालन भी किया तो उसे शबासी देने के विपरित आयोग के आयुक्तों ने उसे अप्रत्यक्ष रुप से पत्राचार से हड़काने की कोशिश भी की।

मु.सू.आ. का ये कथन कि धारा ४ को परा करवाना और शासन से पूरा करवाने के लिए पूछताछ करने के बारे में जानकारी नहीं थी।यह बूढ़ा लालची स्वयं नहीं चाहता कि धारा ४ पूरी की जाए। क्योंकि धारा ४ के पूरा होते ही ९० प्रतिशत अपीलें आना ही बंद हो जाएगी और इनके दोनों हाथों से बटोरने के मौके हाथ से जाते रहेंगे कई विभागों से मिलने वाला महीना जिसमें मप्र वाणिज्यकर आबकारी के साथ परिवहन विभाग, मप्र विद्युत मंडल उसकी पांचों कंपनियां, मुद्रांक एवं पंजीयन, राजस्व, भू अभिलेख, आदिम जाति कल्याण, व अन्य सभी शासकीय विभाग जो सूचना अधिकार के लपेटे में आ चुके है। जानकारी जनता के हाथ न पड़ जाए अन्यथा इनका भ्रष्टाचार की सारी सच्चाइयां सार्वजनिक होने से कईयों की नौकरियां चली जाएंगी और शासन को लेने के देने पड़ जाएगे।

श्री अजमेरा ने आयोग को अभी तक दो सौ से ज्यादा अपीलें सन् २००६ से अभी तक लगाई और हर अपील में धारा ४ को पूरा करने के एि हर विभाग के बारे में लिखा। इन हरामखोरों ने ९० प्रतिशत अपीलें अनावेदकों से धन वसूलकर रद्द कर दी जबकि सब अवैध थीं। क्योंकि बिना वैध कारण के तो अपील ही नहीं लगाई जा सकती ।

दूसरी ओर आयोग अपील पर अनावेदक से स्पष्टीकरण मांगता है। उस अपील की कापी के साथ पर स्पष्टीकरण मांगने में ही दूरभाष पर या सीधे ही मिलकर लेने-देन का खे हो जाता है। यदि लेने-देन पर्याप्त स्तर का हो गया तो फिर अपील में कितने ही ब्लेंक तथ्य हो। उसे रद्द करना या अधिकततम धारा ७(६) में चाही गई जानकारी मुफ्त उपलब्ध करवाने से ज्यादा पिछले ५ वर्ष में ५० जिलों के ५००० से ज्यादा अधिकारियों पर मुश्किल से ५-६ को ही धारा १९(८)सी में दंड दिया गया।

वैसे आयोग को अनावेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति आवेदक को भेजनी चाहिए पर ये हरामखोर जालसाज सीधे ही स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवेदक को बिना स्पष्टीकरण की प्रति भेजे बिना ही आवेदक की आज्ञानता का फायदा उठाकर अपील की सुनवाई का बुलावा भेज कर एक तरफ ही लेन कर खेलकर डालते है। जबकि प्राकृतिक न्याय के नियमार्तग जैसे आवेदक की अपील पर अनावेदक से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। वैसे ही अनावेदक के स्पष्टीकरण की प्रतिआवेदक को भेजे बिना अपील की सुनवाई कर लेते है। जबकि आवेदक को अनावेदक के स्पष्टीकरण के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता और सीधे सुनवाई में बिना कुछ बिना ये आयुक्तों की फौज एक तरफ निर्णय आयोग की पूरी कार्यवाही की अवैध हो जाती है। इसके साथ ही ९० दिनों में अपील की सुनवाई की अपेक्षा डेढ़ से दो सा लगाया जाता है जब तक आवेदक के सूचना मांगने का औचित्य ही अर्थहीन हो जाता है।तीसरा आयोग में पत्रों, अपीलों का पंजीयन भी डेढ़ से दो माह बाद किया जाता है। इन हरामखोरों की जालसाजी का उत्कृष्ट नमूना हे। जो ये कदम-कदम कर रहे है।

बाकी अगले अंकों में

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से प्रधान संपादक

लो.नि.वि. में फर्जी जाति के आधार पर नौकरी

सिंग बंधु कब तक नौकरी फर्जी जाति प्र.प. के दम पर

मु.अ. एम.पी.सिंग का अ. सीपी सिंग निवासी धार के जाति प्रप. बिलासपुर से

इंदौर। मप्र लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में मुख्य अभियंता का प्रभार संभाल रहे एमपी सिंग, पूर्व के इंदौर संभाग के सेतु का इसका भाई सीपीसिंग जो वर्तमान में भोपाल मप्र पुलिस हाउसिंग बोर्ड में कार्य पालन अभियंता है। के जाति प्रमाण पत्र बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बनवाए गए है। जबकि दोनों मूल निवासी धार जिले के निसरपुर के रहने वाले है।

इस संबंध में प्रमुख अभियंता शैलेन्द्र शुक्ला जो सेवा निवृत्ति के बाद सेवाकाल विस्तार के बिस्तर पर लेटकर हर आबंटन, स्वीकृति और हर कार्य में दोनों हाथों से वसूली में जुटा है। सूचना के अधिकार में पत्र दिया गया था। जिसमें मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र ही मूल रुप से मांगे गए थे। धूर्त पत्र ही हजमकर गया बेशक दोनों हाथों ऐसे सभी फर्जी लोगों से जो विभाग में कार्यरत है। दोनों हाथों प्रकरण दबाने और जवाब देने में वसूली की ही होगी। फिर अपील प्रस्तुत की गई। ये जालसाज शुक्ला इसे भी पी जाएगा। वैसे भी ये पहला जालसाज विद्युत यांत्रिकीय का पहला अभियंता है, जो कि न केवल सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री धारक नहीं होने के बाद भी न केवल पूरे लोक निर्माण विभाग का प्रमुख अभियंता पद पर भी सेवा निवृत्ति के बाद भी पदस्थ है। इस धूर्त को सिविल इंजीनियरिंग कीमते ही अबसद नहीं आता हो परंतु हर निविदा में, संभागों के धन आबंटन में, हर कार्य में निश्चित दरों पर कमीशन वसूली का अवश्य विशेषज्ञ है। स्वाभाविक ऐसा धूर्त हरामखोर आवेदक को जानकारी देगा या ऐसे जालसाजों से वसूली करने का अधिकार सुरक्षित करेगा।

इस संबंध में एक आवेदन मुख्य अभियंता पश्चिम क्षेत्र, मप्र लोक निर्माण इंदौर को भी दिया गया था। पर इस बिंदु की जानकारी देने में इस कार्यालय में जालसाजी के साथ व अन्य संभागों ने भी जो इस पश्चिम परिक्षेत्र में आते थे ने भी जालसाजी करते हुए जानकारी देने की अपेक्षा उल्टे ही हरामखारों ने उल्टी सीधी दलीलें दी या अधिकांश ने जवाब ही नहीं दिए। समय माया के पाठक जानते है। कि सचिवालय लोक निर्माण विभाग भोपाल से ३१.१२.०९ को ही प्रदेश के १ मुख्य अभियंता कार्यालय बंद करने के आदेश हो चुके थे उस समय माया ने लगातार मई ०९ से ही रोकने

की अकेले दम पर ही मुहिम चलाकर बंद होने से बच गया था ऐसे ही लोनिवि की सारी सड़के जो राज्य मार्ग से सड़क विकास निगम ने छीन लिए। भवन निर्माण कार्य संबंधित विभागों को सौंप कर इस प्रदेश के पूरे लोनिवि को बंद करने की ही तैयारी चल रही थी। उसमें भी अकेले ही समय माया ने अपनी मुहिम चलाकर रोका और सलेमान की विदाई उसके न चाहने के बाद भी करवाई। इसके विपरीत इस विभाग में उपर से नीचे तब बैठे डकैतों को इन सब से कोई सरोकार नहीं।

जानकारी न देने के लिए अधिकारियों का हथकंडा

ग्रा.यां.से.के का.अ. गौर द्वारा स्टिंग आप्रेशन

देवास। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व अन्य शासकीय कार्यों मदों में चल रही लूटपाट और भ्रष्टाचार की कहानियों का पत्रकारों द्वारा छापा जाना या उसके भ्रष्टाचार को कैमरें में कैद करने के स्टिंग आप्रेशन तो जनता ने टीवी समाचार पत्रों में पढ़े देखें और सुने होंगे।इसके विपरीत शासकीय अधिकारियों द्वारा अपने भ्रष्टाचारों को दबाने, सूचना अधिकार में जानकारी न देने, आवेदकों, पत्रकारों पर ब्लेक मेलिंग का आरोप लगाकर बचने के लिए अब अधिकारी भी जेबों में, टेबल पर पेन स्टेंड में, घड़ी में, कालर में, मोबाइल फोन से कैसे स्टिंग आप्रेशन करते है। इसका दिनांक २५.८.२०१० को देवास के मप्र ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा के कार्य पालन अभियंता जेपी गौर ने दोपहर ३ बजे से ५ बजे के बीच अपने कार्यालय में अंजाम दिया।इस हरामखोर जेपी गौर ने ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा ने पंचायत के कार्यों जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों में रु.५ लाख से ज्यादा के कार्यों में, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में करोड़ों के कार्य संपन्न किए। उसकी जानकारी सूचना के अधिकार में मांगी गई। जानकारी के नाम पर बंदे ने सौदेबाजी की कोशिश की, और सौदेबा के नाकाम होते-होते महीना गुजर गया अपील मुख्य कार्य पालन अधिकारी देवास को की गई। जहां ये निर्णय हुआ कि धारा ७(६) के अंतर्गत मुफ्त में दी जाए।

जानकारी की अपेक्षा फिर सौदेबाजी की कोशिश की गई। जब सारी कोशिशें नाकाम रही तो इस धूर्त ने बड़े बिलों की फोटोकापी में से जो एक ही पार्टी के तीन अलग-अलग

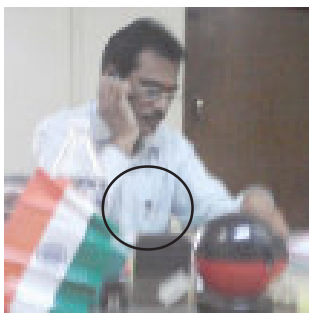

नामों से थे, बिलों में से पार्टी के नाम ही फोटोकांपी में जालसाजी करते हुए उड़ा दिए। दूसरी ओर जानकारी देने में स्पष्ट निर्देशों के बाद में भी इस जालसाज ने अपने वकीलों की सलाह पर किसी भी दास्तावेज को सत्यापित नहीं किया, न ही सूचना के अधिकार में प्रदत होने की मुहर लगाई।

जबकि इस जालसाज के अंतर्गत देवास उपखंड के साथ कन्नौर बागली सोनकच्छ खातेगांव टोंक खुर्द, हाटपिपल्या, जैसे ८३४ संभाग हे। जहां करोड़ों रु. के कार्यो को जालसाजी पूर्ता तरीके से संपन्न कर करोड़ों रु.डकारा जा रहा है। इसलिए ये जालसाज किसी भी दस्तावेज को न केवल सत्यापित नहीं कर रहा उल्टे ही जब शिकायत करने पहुंचे तो स्टॉफ का कहना था कि अजमेरा जी कहां परेशन कर रहे हो और हो रहे हो गौर साहब सा समझौता कर, कराके नक्की करो। इसके उपरांत उन बिलों की कापी जिसमें पवन इंफ्रासूक्चर, पवन सेल्स, पवन मार्केटिंग के तीन माह के ही करोड़ों रु. के सीमों आपूर्ति के बिलों में उपर मुख्य पार्टी के नाम वाले हिस्से को जालसाजी पूर्ण तरीके से उड़ा दिया गया और सीमेंट के बिल पास करने के साथ साइट से मिली जानकारी के अनुसार आधी से ज्यादा सीमेंट की वहीं सौदे बाजीकर बेंच दिया गया था इसलिए पूरे बिल की फोटो कापी नहीं दी गई थी जब २५.८.१० को बात करने पहुंचे ये कार्य पालन अभियंता श्री अजमेरा का स्टिंग आप्रेशन करने की नियत से जेब में पेन लगाकर बैठे थे। जब अजमेरा ने पूछा तो कहते है कि मेरे लड़के का है ये पेन उसने दिया था तो जेब में लगा लिया। जब पूछा गया कि बिलों की ऐसी फोटोकापी क्यों की गई तो बोले फोटोकापी मैंने नहीं करवाई है। जबकि उसका स्पष्ट उद्देश्य था, कि श्री अजमेरा को उकसाकर ऐसी रिकार्डिंग की जाए जिसमें आसानी से ब्लेकमेलिंग का आरोप लगाकर न केवल दस्तावेज देने से मना किया जा सके। वरन उल्टे ही फंसा कर प्रकरण लादा जा सके। जबकि इस जालसाज की इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जांच करवाने के लिए लोकायुक्त प्रकरण में लादा जा सकता है। यदि रिकार्डिंग कर भी लेता है। तो अभी तो कटघरे में स्वयं ही खड़ा है। जबकि यही आवेदन की फोटोकापी दूसरे पत्रकारों को बांटकर ज्यादा फजीहत खड़ी की जा सकती है तीसरा ये मात्र बागली उपसंभाग के बिलों की ही फोटोकापीयां दे रहा है जबकि देवास, टोंकखुर्द, कन्नौद, खातेगांव, सलास, हॉटपिपल्स के उपसंभागों के बिलों और कार्यों दस्तावेजों की फोटोकापियों का पता ही नहीं है।जनता देखे कि जनहित की लड़ाई लड़ने वालों को ये धूर्त मक्कार जालसाज शूकरों की फौज फंसाने के लिए कैसे हथकंडे अपनाते है। फोटों में का.अ. की जेब में लगा पेन कैमरा, गोले में।

जहां बाड़ लगाई वही खेत खाने लगी

अविश्वसनीय भारत

हमारा राष्ट्र अविश्वसनीय राष्ट्र। कहीं उत्कृष्टतम तो कहीं विश्व के निकृष्टतम।

हजारो वर्ष की गुलामी में रहने वाला एक राष्ट्र महान भारत। जिसे ६० वर्ष भी आजादी हजम नहीं हुई, और पुनः सत्ताधीशों जिन्हें जनता ने वोट देकर बैङ्गाया कह सकते हैं। बाकी जीते तो वोटिंग मशीन की जालसाजियों से ही है। जीतने के बाद कुछ बेहतर करके दिखाते तो भी जालसाजी की वह जीत हजम हो जाती परंतु वा निकम्मे भ्रष्ट, आत्मविश्वास और स्वाभिमान हीन कागज के टुकड़ों की खातिर, कमीशन खोरी और विदेशी बैंकों में अपनी रकम के अंकों में बढ़ोत्तरी के लिए राष्ट्रहित और जनता कर गला घोंटकर पुनः विदेशियों को अपत्यक्षरुप से सत्ता सौंपने और गुलामी को आमंत्रित करने की चाले चलने लगे।

हम १२५ करोड़ की आबादी के देश को उस २६ करोड़ के संकर प्रजाति के अमेरिका के सामने नाचते है। उसके सामने कटोरा लेकर उसके दान के सहारे जीते है। सर्वश्रेष्ठ कृषि उत्पादों, औद्योगिक उत्पाद और प्राकृतिक उत्पादों को उसकों भेंट कर देते है। और इस देश के १२५ करोड़ जानवरों में से लगभग ४० करोड़ वहां का सड़ा गेहूं, दालें, तेल, शकर आयात करके पेट भरते है। जबकि ये १२५ करोड़ हाथ फैला दें। तो कई अमेरिका इसकी मुठ्ठी में आ जाए। पर इस भारत की यही

अविश्वसनीयता है, कि वो हाथ समेटने के लिए नहीं वरन् भरत मांगने के लिए फैलाए जाते है। यहां की १२५ करोड़ जनता उनको सत्ता आंख मींच कर सौंप देती है जिनके पास न तो आत्मविश्वास होता है न आत्मस्वाभिमान। जो कभी अमेरिका के इशारे पर नाचते है। तो कभी ब्रिटेन के इशारे पर और नहीं तो उनके षड्यंत्रों के तहत बैङ्गाई गई सोनिया जो विरुद्ध युरोपियन एजेन्ट है, के इशारों पर नाच ने से भी कोई परहेज नहीं करते धन्हय हे१२५ करोड़ गुलामों का देश।

जिन्हें न्याय की बागड़ोर सौंपी जाती है। वो केवल अपनी जेब, अपने परिवार के सुख समृद्धि के साथ न्याय करते है। यहां २०००० लोगों को मौत की नीद सुला देने वाला शान से आता है। शान से नोटों रुपी कागज के टुकड़े फैकता है। तो मालूम पड़ता है। कि क्या पुलिस क्या न्यायालय क्या मंत्री, मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति सब उसकी बलैंया उतार कर, उसे शान से हवाई हड्डे तक छोड़ने भी जाते है। मुकदमों चलाया जाता है। सब हुकड़खोर टुकड़े तोड़ने आते है। चले जाते है २६ वर्ष बाद फैसला सुनाया जाता है। तो मात्र लापरवाही का ही दोषी पाया जाता है।

जनता के स्वास्थ्य के लिए अरबों रु. खर्च किए जाते है। जनता का स्वास्थ्य सुधरे न सुधरे, परंतु डाक्टरों से लेकर मंडियों तक के बैंकों के बैलेंस के न केवल स्वास्थ्य सुधर जाते है। वरन् उनके मोटे बैलेंसो की मोटाई घटाने के लिए विदेशी बैंकों को भेजना पड़ता है। जनता साधु सन्यासियों की झाड़ फूंक और भभूतियों से ही ङ्बीक होकर काम चला लेती है। हे न, अविश्वसनीयता भारत में चारों तरफ।

जिन पुलिसियां और जांच एजेंसियों को जनता की सुरक्षा सौंपी जाती है उसके ही एसपी डीएसपी तक को सुरक्षा के लिए पहले ही चार-चार पुलिस वाले सुरक्षा के लिए चाहिए पड़ते है। उन्हें अपराध रोकने के लिए कहा जाता है, वे स्वयं ही अपराधियों के साथ मिलकर अपराधों के सरगना बन जाते है। मुंबई में हमला हुआ उन्होंने सबसे पहले ही अपने ही साथियों को मार डाला मुङ्गभेड़ की आड़ में, फिर मुङ्गभेड़ स्थल पर पहुंचे और स्वयं ही चिल्लाने लगे कि मुङ्गभेड़ में मार दिए गए। जनता की सुरक्षा की बात तो कोसों दूर गई। यहां कानून बनाए जाते है। जन हित के नाम पर, पर होता इसके ङ्बीक विपरीत ही है। कानून की छड़ी उङ्काकर जनता को चमकाया जाता है। और उगाही का हथियार बन जाते हे। वैसे भी कानून, धूर्तों के बनाए शब्दों क माया जाल है। जो अपनों को बचाने और निरीहों के शोषण के काम आता है।

इन सबके साथ ही १९७० के बाद जितने भी कानून बने वो सब बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर उनके लिए ही बने या फिर सत्ताधीशों की वसूली के लिए ही बनाए गए।

यहां जिसको सत्ता सौंपी जाती है। सत्ता प्राप्त करते ही वह जनहित नाम का शब्द कोष मस्तिष्क के शब्द कोष से तुरंत बाहर कर देता है। और स्वाहित में जुट जाता है। इसके लिए वह सफेद खादी पहनकर सारे काले, कुकर्मो में जुट जाता है। यहां उसे अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता और सत्ता में बैङ्गते ही अपने अधिकारों की आड़ में धन वसूली करता हुआ। सत्ता का सूरत भोगता है। सत्ता, कांटों का ताज नहीं कमाइ का राज और सीज बन जाती है। फिर बाढ़ खेत खाने लगती है।

हमारा राष्ट्र सहस्त्रों वर्षों से गुलाम रहा है।

तो मात्र घोर स्वार्थी मानसिकता और आत्म विश्वास की कमी के कारण। राष्ट्र प्रेम की अपेक्षा सदा से ही स्वप्रेम स्वकल्याण यहां के जनमानस की नियति बनी रही। इसके चलतें जो भी आया आसानी से हम पर राज करता रहा। और हम उसकी गुलामी करते रहे। तो हमारे देश की धरती पर हमें ही जोतता रहा और हम उसकी गुलामी करके अपने भाग्य को सराहते रहे। दुनिया को ज्ञान बांटने वाला यह राष्ट्र स्वयं कितना बड़ा अज्ञानी रहा।

इसके विपरित हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा और मात्र ६० वर्ष की आजादी शैशत अवस्था से बाहर निकलकर स्वयं के पैरों पर चलना भी नहीं सीख पाई थी कि हमारे लालची सत्ताधीश अपने ही खजाने में डकैती डालकर विदेशी बैंकों में धन छुपाने लगे। दूसरी ओर आर्थिक अभाव का रोना रोकर विदेशी बैंकों से कर्ज लेकर घी पीते हुए सत्ता सुख भोगते रहे। साथ ही इस कर्ज के नाम पर देश के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों को गिरवी करते रहे।

नेहरू ने दो, इंदिरा ने तीन, सोनिया चौथा टुकड़ा करेगी भारत का

काश्मीर को स्वायतत्ता, अर्थात नया देश

मन मोहन ने काश्मीर को नया देश बनाने का राग अलापा

वर्तमान में भारत की सत्ता में बैङ्गे धूर्त कांग्रेसी डकैतों को राष्ट्र क संसाधनों को येन केन प्रकरण निचोड़ कर स्विस बैंकों में जमा करने के अतिरिक्त सावन के अंधों की भांति देश के संसाधनों की वर्तमान कमाई की हरियाली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिख रहा। इसके परिणाम स्वरुप पूरे राष्ट्र में न केवल आम जनता को एक तरफ महंगाई की भारी चोट लग रही है। तो दूसरी तरफ इस से मोटा कमीशन हर वर्ष उकारने के लिए राष्ट्र का पूरा खाद्य उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने के लिए कानून ही बना दिया। जबकि इसके लागू होने से लगभग १० करोड़ लोग निश्चित तौर पर बेरोजगार हो जाएंगे।

इसी प्रकार बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मप्र, बिहार,छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां खनिजों का भंडार है।जहां आदिवास खेती करते है उनकी जमीने आधा अधुरा मुआवजा, या बिना मुआवजे के जमीनों पर मोटा कमीशन खाकर गृहमंत्री चीट अंबर और राज्यों के मुख्यमंत्री जिसमें छग का रमन वैसे, मप्र का चौहान उड़ीसा का बीजू पटनायक बिहार का भरद्वाज, बंगाल का भ्रष्टाचार्य के साथ मिलकर उन जमीनों को खनिज माफियाओं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों वेदांत, टाटा,हिंडालको जिंदल जैसों को सौंप दिया जब आदिवासियों ने एक जुट हो सरकारी नीतियों का विरोध किया तो फर्जी मुङ्गभेंड़ों में आजाद जैसे नेताओं का मार डाला गया। ऐसी सैंकड़ों इन कांग्रेसी डकैतों की कारस्तानियों पर अंगुली उङ्गने लगी तो काश्मीर की स्वायतता का राग अलापकर जनता और राष्ट्रीय पार्टियों का ध्यान बांट दिया।

जबकि वहां के मुस्लिमों को आतंकवादियों को साथ मिलाकर सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंकना इन कांग्रेसी जालसाजों ने ही सिखाया और पैसे देकर उन्हें पत्थर फेंकने का रोजगार देकर वहां से काश्मीरी पंडितों सिवरवों का भगाना शुरु कर दिया। कांग्रेस की फूट डालों और राज करों की नीतिका अनुसरण कांग्रेस ने अपने आकाओं से ही सीखा है।

नेहरू की अय्याशियों, रंगरैलियों और रंगीन मिजाजी का ही परिणाम था भारत के दो टुकड़े होना। वह पाकिस्तान अलग होकर ३६ वर्ष बाद भी लगातार तकलीफ दे रहा है। नेहरू की अय्याशियों का ही परिणाम था काश्मीर को पूरे भारत में धारा ३७० के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा किया गया। और अब्दुला को जो कि नेहरु की अय्याशी की औलाद कहा जाता है। स्वतंत्र राज्य का दर्जा देकर वहां का प्रधान मंत्री बनाया गया ताकि नेहरू की ज्यादा बदनामी न हो।

१९६९ में इंदिरा गांधी ने रुस के माध्यम से शास्त्री के दूध में जहर मिलवा कर देकर मरवा दिया और सत्ता संभालते ही उसने देश के छोटे-मोटे, राजाओं की संपत्तियों पर डकैती डालकर हड़पना शुरुकर दिया। जब ज्यादा हल्ला मचा तो १९७१ में युद्ध के माध्यम से पूर्ती बंगाल को बांग्लादेश बनाकर तीसरा टुकड़ा कर दिया जिसे आसानी से भारत में मिलाया जा सकता था। वर्तमान में पूर्वी भारत के बंगाल से लेकर आसाम तक हमारी सीमाओं पर वह भी तांडव कर रहा है सन् ८० से इसके बाद १९७५ में अपनी घोर दमनकारी नीतियों लूट खसोंट की मानसिकता के चलते उसने खालिस्तान फोर्स और भिंडरावालां को हता दी जो ३१.१०.८४ को स्वयं इंदिरा की मौत का कारण बना।

बाद में राजीव आया तो उसने आते ही लिट्टे को पालपोसकर अमेरिका की बड़ा किया लंका में तांडव करवाया और बाद में अपने ही देश के तमिहों को भारतीय शांति सेना के माध्यम से लाखों की संख्या में मरवा डाला। जो बाद में राजीव की मौत का कारण बना।

अब गांधी खानदान की देश लूटने वाली डकैत बहु और युरोप की एजेन्ट सोनिया अपनी कङ्गपुतली प्रधान मंत्री मनमोहन अपनी महंगाई, खनिज भंडार बेंचने और सौंपने, अपनी नाकामियों को छुपाने काश्मीर को स्वायतत्ताप के माध्यम से अलग कर भविष्य में बांग्लादेश की तरह नया राज्य बनाने का षड्यंत्र कर रहा है। पहले स्वायतत्ता का राग अलाया, फिर जम्मु काश्मीर की अलग मुद्रा का राग अलाया, कल सेना और संविधान का राग अलाएगा। परसों अलग राष्ट्र के रुप में मान्यता देकर आंख फेर लेगा।

फिर राहुल आएगा तो अपनी मां इटालियन बिल्ली और युरोपीय एजेन्ट सोनिया अपनी दादी इंदिरा, पड़ दादा नेहरु की तरह पूर्वोत्तर चीनियां को सौंप देगा। नक्सलियों के लिए पूरे भारत में एक नया राष्ट्र की घोषणा कर देगा जैसे ये देश नेहरू गांधी के पुरखों की जायजाद हो।

लोकायुक्त, ईओडब्ल्यु, सीबीआई, भ्रष्ट दुकानदारी

भारत में जांच एजेंसियों की नौटंकी

अपराधी मस्त, फरियादी त्रस्त, मामले अटकाने लटकाने के विशेषज्ञ

हमारे राष्ट्र में जनता के आक्रोश को ङ्बंडा करने अपनी खाल बचाने अपनी छवि बनाने और बचाने के लिए सत्ताधीश मंत्री, नेता और उच्च स्तरीय अधिकारी किसी भी प्रकरण में जांच एजेंसियों का गठन कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। जांच एजेंसियों में चाहे लोकायुक्त, ईओडब्ल्यु हो, सीबीआई हो, जांच आयोग हो, अधिकारी हो, ९०प्रतिशत जांच एजेंसियों में व्यक्तियों के स्तर, सत्ता का असर, संबंध, लेन देन के आधार पर ही सारी जांच होती है। फिर इन जांचों का सीधा सा उद्देश्य होता है सत्ताधीशों के इशारे पर ही सारे कार्य संपन्न होते है। जानबूझ कर जांचों के नाम पर वर्षो गुजार दिए जाते है, सत्ताए पलट जाती है, या आती और जाती है। अधिकारियों और नेताओं को खुलालेन देन कर बचाया जाता रहता है।

इसके विपरीत इस देश के बड़े औद्योगिक घरानों जैसे रिलांयस के मुकेश और अनिल अंबानी, टाटा समूह, सहारा, आईटीसी, बिरला, सुनील मित्तल, जिंदल, जेपी, जैसे अरबों रु. के घोटाले करने वालों, जनता को लूटने वालों, जमीनों पर अवैध कब्जे करने, ग्रामीणों, वन विभाग, नजूल की, शासकीय भूमि, शासन के धन, करों आदि को डकार जाने वाले के विरुद्ध भी कई

हाथ नहीं डालता। जबकि ये अरबों रु. के घोटाले दूर संचार, पेट्रोल, कस्टम एबसाइज, आयकर से लेकर और अधिकांश बड़े-बड़े पूंजीपति, व्यवसायी जो जहां पर जिस व्यवसाय को देख या कार्यकर रहे है। सब कुछ जहां जैसा मौका मिला कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सारे कुकर्म कर रहे है। इसमें आई डीबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई सी आई बैंकर्स, से लेकर बड़े राष्ट्रीय कृत सभी २८ बैंकर्स, बीमा कंपनियां, दूरसंचार, पेट्रोल गैस कंपनियां, सभी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में अवैध कार्यों को संपन्न करने में लिप्त रहने के बाद भी, शासन को अरबों रु. की चोट पहुंचाने के बाद भी शान से न केवल जिंदगी जी रहे है। वरन शिकार पर शिकार, कुकर्मो पर कुकर्म किए चले जा रहे है। परंतु कोई कुछ नहीं बोलता। यदि ये बड़े-बड़े पकड़े भी जाते है तो छोटो को

शेष पेज ५ पर...

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस. पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित.
भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भारद्वाज मो.94256-37958, इन्दौर कार्या. फोन 2530859 मो. 93007-55803